वर्ष : 16 ❖ अंक : 51 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
बुधवार, 22 सितम्बर 2021

आप असली है, बीजेपी नीतियों की नकल कर रही है : केजरीवाल 3

महंत नरेन्द्र गिरि को योगी-केशव ने दी श्रद्धांजलि 8

25 साल से ठप व्यवस्था को ठीक करने में लगता है समय : सीएम

सरोज गुरुंग

सोरेंग, 21 सितम्बर । पश्चिम जिले के रिन्छेंपोंग के मेघिडांड़ा में रिन्छेन छ्योलिंग गुंपा में आज तीन दिवसीय 'विश्व शांति पूजा' का समापन हुआ। गुंपा समिति ने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की छठी वर्षगांठ के अवसर पर गुंपा में तीन दिवसीय विश्व शांति पूजा का आयोजन किया था। इस धार्मिक समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के साथ मंत्री लोकनाथ शर्मा, मंत्री सोनाम लामा, मंत्री भीमहांग सुब्बा, विधायक आदित्य गोले, विधायक सुनीता गजमेर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जैकब खालिंग, सांसद इंद्र हांग सुब्बा, गुंपा के प्रमुख टुल्कु सांगे योंतेन ग्याछो रिम्पोछे, मुख्यमंत्री के सलाहकार राज रोहित महाराज आदि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि इसी साल 3 मार्च को भी मुख्यमंत्री गोले ने रिन्छेन छ्योलिंग गुंपा का दौरा किया था। मुख्यमंत्री गोले का यह दूसरा दौरा है।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने सरकार की ओर से सभी को विश्व शांति दिवस 2021 की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कभी भी राजनीति के साथ गुंपा, मंदिर या चर्च जैसे किसी धार्मिक स्थलों जोड़ने का काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार एक ऐसी सरकार है जो लोगों के हित में राजनीति करती है। जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो पवित्र हृदय लेकर चलते हैं।

उन्होंने कहा कि हमने किसी भी धार्मिक, सामाजिक और जातीय आयोजन में पार्टी का झंडा फहराने की प्रथा को बंद कर दिया है। सरकारी कर्मचारी अब बिना किसी डर के कार्यक्रम में स्वतंत्र रूप से शामिल हो सकते है। हम बिगड़ती व्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। 25 साल से ठप पड़ी व्यवस्था को ठीक करने में समय लगता है। हम पांच साल के भीतर सिक्किम के लोगों को प्रगति रिपोर्ट सौंपेंगे।

मुख्यमंत्री गोले ने दावा किया कि एसकेएम सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि एसकेएम सरकार सिक्किम के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए आई है। सिक्किम के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न स्तरों से सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता और विश्व प्रसिद्ध कवि रवींद्रनाथ टैगोर के प्रति भी

श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने यहां रवींद्रनाथ टैगोर की 36 फुट ऊंची प्रतिमा के निर्माण की भी घोषणा की। ज्ञात हो कि दिवंगत कवि टैगोर ने 1913 में रिन्छेंपोंग पीडब्ल्यूडी डाक बंगलो में आकर रचनाएं लिखीं थी। टैगोर के सम्मान में स्थल पर एक मूर्ति स्थापित करने की समय-समय पर मांग उठाई जाती रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों की मांगों को देखते हुए यह घोषणा की।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने 31 करोड़ रुपये की लागत से रिन्छेन छ्योलिंग गुंपा परिसर को विकसित करने की भी घोषणा की। उन्होंने 15वें वित्त आयोग से देंताम बाजार के पास सिंगसोर ब्रिज को 85 करोड़ रुपये की लागत से शीशे का पुल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार सिक्किम के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

गुंपा के प्रमुख रम पावन टुल्कु सांगे योंतेन ग्याछो रिम्पोछे ने छह साल पहले 21 सितंबर को गुंपा में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान किया था। तब से यहां हर साल 21 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस भी है। इन विविध मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन दिवसीय विश्व शांति पूजा 19 सितंबर को गुंपा में शुरू की गई थी।

रिन्छेन छ्योलिंग गुंपा की स्थापना 1996 में हुई थी। वर्तमान में गुंपा का संचालन एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पीएस गोले ने सरकार की ओर से गुंपा को 50 लाख रुपये प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह पश्चिम जिले के देंताम बाजार के पास मांगमू में टुल्कु सांगे ग्याछो रिम्पोछे की अवधारणा पर बनने वाली गुंपा 'गुरु पद्मसंभव बौद्ध शिक्षा अध्ययन एवं ध्यान केंद्र' के नाम से जाना जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में कोष आवंटित कर केंद्र की स्थापना करेगी। सेवानिवृत्त एसीएफ गजेंद्र सिंह गुरुंग ने इस धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए जमीन दान में दी थी। कार्यक्रम में गुरुंग को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को मंत्री सोनाम लामा, मंत्री लोकनाथ शर्मा, सिक्किम मेडिसिन ख्लांट बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गुरुंग और गुंपा कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण गुरुंग ने भी संबोधित किया।

आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर शोध जरूरी : राज्यपाल गंगा प्रसाद

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 21 सितम्बर । राज्यपाल गंगा प्रसाद ने आज देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट आफ टिबेटोलॉजी (एनआईटी) का दौरा किया। राज्यपाल का स्वागत संस्कृति मंत्री साम्डुप लेप्चा, एनआईटी की निदेशक पीडब्ल्यू रिंजिंग और अन्य अधिकारियों ने किया। यह जानकारी राजभवन ने दी है।

राज्यपाल ने अपने संक्षिप्त संबोधन में आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर और शोध करने पर जोर दिया और कहा कि दुनिया में आयुर्वेद का उपयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता है। आयुष मंत्रालय पहले से ही पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के तहत आयुर्वेद और अन्य जड़ी-बूटियों को बढ़ावा दे रहा है।

राज्यपाल ने संस्थान के विकास के लिए अपनी ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की। राज्यपाल ने मंत्री लेप्चा और राजभवन सचिव के साथ एनआईटी में हर्बल उत्पादन इकाई का भी दौरा किया। इससे पहले एनआईटी के निदेशक ने चल रही परियोजनाओं पर प्रगति रिपोर्ट पेश की और राज्यपाल से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।

क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ने शुरु किया पोषण अभियान

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 21 सितम्बर । क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गंगटोक, सिक्किम की ओर से आज नर बहादुर भंडारी सरकारी कॉलेज, तादोंग में राष्ट्रीय पोषण माह-सितंबर 2021 के कार्यक्रम के तहत किशोरियों के लिए पोषण में आयुर्वेद एवं योग का महत्व विषय पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) को शुरू किया गया।

आरएआरआई, गंगटोक ने विभिन्न गतिविधियों जैसे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के लिए जागरुकता व्याख्यान के साथ-साथ पौष्टिक भोजन और आईईसी सामग्री के मुफ्त वितरण किया। उक्त कार्यक्रम के मौके पर संबंधित विषय पर एक व्याख्यान एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थान प्रमुख सहायक निदेशक (आयुर्वेद) डॉ श्रीप्रकाश ने किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जीटी ढुंगेल थे। श्री ढुंगेल ने अपने संबोधन में कोविड-19 से बचाव एवं चिकित्सा हेतु संस्थान द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की उन्होंने स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित छात्राओं से उत्कृष्ट समाज के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने और स्वस्थ रहने के लिए योग (शेष पृष्ठ ०३ पर)

वनजात बच्ची जंगल में मिली

सरोज गुरुंग

सोरेंग, 21 सितम्बर । सोरेंग के पास सिंगलिंग में एक नवजात कन्या जंगल में मिली। किसी ने बच्ची को जन्म के बाद जंगल में फेंक दिया। शिशु का स्वास्थ्य अच्छा है और उसे सोरेंग अस्पताल में रखा गया है। सोरेंग पुलिस घटना की जांच कर रही है। बच्ची को जन्म देकर फेंकने वाली महिला का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।

सीएम की कार्यशैली देखकर हतोत्साहत हो गए है पवन चामलिंग : तामलिंग

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 21 सितम्बर । सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिंग द्वारा एसकेएम सरकार और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है।

एसडीएफ पार्टी अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की निंदा करते हुए एसकेएम प्रचार उपाध्यक्ष प्रभारी बीरेंद्र तामलिंग ने आज जारी एक प्रेस बयान में कहा है कि एसकेएम पार्टी और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की कार्यशैली और दक्षता को देखकर और मुख्यमंत्री को खुद लोगों की सेवा करते देख लोग एसडीएफ पार्टी छोड़ रहे हैं और एसकेएम पार्टी में शामिल हो रहे है, लेकिन चामलिंग कांट्रैक्ट का पैसा नहीं मिलने पर एसकेएम में शामिल होने की बात कही है तो निराधार है। चामलिंग का उपरोक्त कथन भी इस बात की पुष्टि करता है कि उनके कार्यकाल में कई ऐसे ठेकेदार थे जिनके बिल का भुगतान नहीं किया गया था। एसकेएम सरकार किसी ठेकेदार का पैसा नहीं रखती है। चामलिंग के कार्यकाल के ठेकेदारों को अभी तक उनके पैसे नहीं मिले हैं, इसका खुलासा चामलिंग ने खुद अपने बयान में किया है।

उन्होंने कहा कि चामलिंग ने वर्तमान सरकार को 'राम राज्य' कहा है। यह कहकर उन्होंने अपने कार्यकाल को 'रावण राज' प्रमाणित कर दिया है। सिक्किम के लोगों को उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिलता था। लोगों को यह भी नहीं पता था कि

मिंतोकगांग कैसा है। लोग बोलने से डरते थे। ऐसे व्यक्ति द्वारा वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर उंगली उठाना सत्ता से गिरने के बाद केवल हतोत्साहित होने का संकेत है।

चामलिंग ने एसकेएम पार्टी के सत्ता में आने के बाद एसडीएफ कार्यकर्ताओं (शेष पृष्ठ ०३ पर)

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए लोग : मन बहादुर छेत्री

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 21 सितम्बर । आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा के रूप में दो दिवसीय कार्यक्रम वाणिज्य उत्सव का उद्घाटन आज हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय आर्थिक शक्ति के रूप में उभरता भारत रखा गया था। इस कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग विभाग के कादो छिरिंग नमका, अध्यक्ष मन बहादुर छेत्री, वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव एचके शर्मा, निदेशक (एमएसएमई) एम रविकुमार, विदेश व्यापार उप महानिदेशक (डीजीएफटी), कोलकाता अमित शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम की (शेष पृष्ठ ०३ पर)

01 अक्टूबर से पाकिम हवाईअड्डे से शुरु होगी नियमित विमान सेवा

प्रवीण खालिंग

गंगटोक, 21 सितम्बर । सिक्किम का एकमात्र हवाई अड्डा, पाकिम ग्रीनफील्ड एयर पोर्ट से आगामी 01 अक्टूबर से नियमित उड़ानें फिर से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली पाकिम, कोलकाता पाकिम और गुवाहाटी पाकिम के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। भारत सरकार की उड़ान योजना के माध्यम से स्पाइस जेट द्वारा उड़ाने संचालित की जाएंगी।

स्पाइस जेट ने कहा कि पाकिम एयरपोर्ट के निदेशक रामतानु शाह से संपर्क कर 01 अक्टूबर से हवाई सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इस बारे में निदेशक शाह ने कहा कि पिछले जुलाई से भारी बारिश के कारण हुई हवाई सेवा को अब फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मौसम पर विशेष ध्यान देते हुए सेवा चालू की जाएगी। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे की सभी स्थितियां सामान्य हैं और यह संचालन के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि जुलाई से नियमित सेवा बंद है परंतु इस दौरान भी कुछ चार्टर उड़ानें कोलकाता से पाकिम उतरीं।

उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से कोविड महामारी के कारण हवाई सेवा को नियमित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। कोलकाता-पाकिम हवाई सेवा शुरू करने के लिए पहल की गई है। वहीं गुवाहाटी पाकिम हवाई सेवा के बारे में उन्होंने कहा कि इसे लेकर स्पाइस जेट का ही निर्णय लेना है। गुवाहाटी से पाकिम के लिए हवाई यात्रा करने वालों की संख्या पहले भी कम रही है और कोविड महामारी के बाद से इसमें और गिरावट आई है। 80 सीटों वाला बॉम्बार्डियर वर्तमान में पाकिम हवाई अड्डे से संचालित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जुलाई में केवल तीन और अगस्त में चार उड़ानें पाकिम हवाई अड्डे पर उतरी थीं। सिक्किम हाई कोर्ट ने भी स्पाइस जेट की कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए इसमें सुधार करने का आदेश दिया था।

देश के 13 हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे चीफ जस्टिस

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। देश के 13 उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 8 नामों की सिफारिश केंद्र से की है। इसके अलावा पांच सिटिंग जज के ट्रांसफर की सिफारिश भी की गई है।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने केंद्र को पदोन्नति के लिए आठ नामों की सिफारिश भेजी है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल शामिल हैं। कोलेजियम ने पांच मुख्य न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश भी की है।

कोलेजियम के इस निर्णय की खबर एजेंसी पहले ही दे चुका था लेकिन इसे न्यायालय की वेबसाइट पर मंगलवार को अपलोड किया गया है।

न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर भी कोलेजियम का हिस्सा हैं।

केंद्र कोलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है तो न्यायमूर्ति बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। उनके अतिरिक्त सात अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनाने की भी सिफारिश की गई है।

शीर्ष अदालत की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया, उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम की 16 सितंबर 2021 को हुई बैठक में न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है।

कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बिंदल के अलावा न्यायमूर्ति रंजीत वी मोरे, सतीश चंद्र शर्मा, प्रकाश श्रीवास्तव, आर वी मलीमथ, रितु राज अवस्थी, अरविंद कुमार और प्रशांत कुमार मिश्रा के नामों की सिफारिश क्रमश: मेघालय, तेलंगाना, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की है।

वेबसाइट पर अपलोड एक अन्य वक्तव्य के अनुसार अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने के लिए पांच मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सूची भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके मुताबिक कोलेजियम ने यह भी सिफारिश की है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए ए कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती को त्रिपुरा उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमद्दर को सिक्किम उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के अलावा कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए के गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर डाले गए तीसरे वक्तव्य में कहा गया है कि कोलेजियम ने 16 सितंबर को हुई बैठक में उच्च न्यायालयों के 17 न्यायाधीशों के तबादले/पुन: तबादले की सिफारिश की है।

प्रधान न्यायाधीश रमण की अध्यक्षता वाला कोलेजियम देश में उच्च न्यायपालिका में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए कदम उठा रहा है और इसी क्रम में उसने इन नामों की सिफारिश की है।

देश में मौजूद 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल 1080 पद हैं जिनमें से एक मई, 2021 तक तक 420 पद रिक्त थे।

महंत के सुसाइड नोट ने छोड़े कई अनुत्तरित सवाल

प्रयागराज, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के सोमवार शाम को कथित तौर पर आत्महत्या करने की घटना ने कई सवालों को जन्म दिया है।

आत्महत्या से भी कहीं अधिक उनके द्वारा छोड़े गए कथित सुसाइड नोट ने कुछ अनुत्तरित सवाल पीछे छोड़ दिए हैं, जिनके उत्तर तलाशना जरूरी है।

लगभग 6 पृष्ठों के सामने आ रहे सुसाइड नोट से पता चलता है कि महंत बहुत परेशान थे, लेकिन यह नोट स्पष्ट रूप से उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करता है, जिन्होंने उन्हें यह चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।

महंत ने कहा है कि वह अपने अलग हुए शिष्य आनंद गिरि और हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के कारण परेशान थे, लेकिन उन्होंने विस्तार से नहीं बताया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'महंत ने इन तीनों से संबंधित विशिष्ट घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, जिससे वह बहुत परेशान थे। हम उन तीनों से अलग-अलग पूछताछ कर रहे हैं, जिन्होंने दिवंगत संत को परेशान किया।'

पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुसाइड नोट का खुलासा करने में बेहद सतर्कता बरत रही है।

इसके अलावा, नोट की सत्यता पर भी सवाल उठाया गया है, क्योंकि संत के करीबी लोगों ने कहा है कि वह एक या दो वाक्य से आगे लिखने में माहिर नहीं थे।

यहां तक कि आरोपी आनंद गिरी ने भी कहा है कि उन्हें फंसाने के लिए सुसाइड नोट छोड़ा गया है।

सुसाइड नोट एक तरह की वसीयत भी है, क्योंकि इसमें महंत की अपने उत्तराधिकार के बारे में अपनी इच्छाओं का उल्लेख किया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, 'पत्र को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है और हम उनकी लिखावट से नमूनों का मिलान करेंगे।'

पुलिस के मुताबिक इस सुसाइड नोट में मठ और अखाड़े के उत्तराधिकारियों के नाम भी लिखे गए हैं, लेकिन इसमें शामिल कंटेंट का अभी खुलासा नहीं किया गया है।

इसके साथ ही 'सम्मान और अपमान' के बारे में भी कुछ बातें लिखी गई हैं।

महंत ने लिखा कि उन्होंने अपना जीवन सम्मान और गरिमा के साथ जिया है और अब वे अपमान नहीं सह सकते।

सुसाइड नोट महंत के शव के पास बिस्तर पर पड़ा मिला था।

सूत्रों के मुताबिक महंत ने वीडियो में एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया, जो अब पुलिस के कब्जे में है।

जानकारी के मुताबिक, 4 मिनट के वीडियो में भी सिर्फ वही कहा गया है, जो सुसाइड नोट में बताया गया है।

लोगों के खुशहाली की राजनीति करती हूं : मेनका गांधी

सुलतानपुर, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। सांसद मेनका संजय गांधी ने अपने सुलतानपुर संसदीय क्षेत्र दौरे के तीसरे और अन्तिम दिन चार गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा के विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों व विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। धनपतगंज ब्लाक स्थित बाढ़ग्रस्त गांव अमऊजासरपुर का नाव से दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया।

सांसद मेनका मंगलवार को बाढ़ ग्रस्त इलाकों का नाव में बैठकर प्रशासनिक अमले के साथ मुआयना किया। बाढ़ से इस समय आधा दर्जन से अधिक गांव डूबे हुए हैं। अमउजासरपुर में लगभग 30 परिवारों का संपर्क शहर से पूरी तरीके से पानी की वजह से कट गया है । ग्रामीणों ने बताया कि जब से बाढ़ आई है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। राशन नहीं मिल पा रहा है। खेत भी डूबने की वजह से फसलों का काफी नुकसान हुआ है। मेनका ने एसडीएम बल्दीराय से तत्काल हर गांव में दो नाव भेजने के साथ राशन सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि हर साल ऐसे ही हालात आ जाते हैं इसके लिए आपदा प्रबंधन फण्ड से एक स्ट्रीमर और फसलों के नुकसान का मुआवजा भी दिलवाया जाएगा।

इसके पूर्व सांसद ने सुलतानपुर विधानसभा के सौरमऊ, देहली मुबारकपुर, अलहदादपुर व बालमपुर में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कहां मुझे राजनीति बिल्कुल नहीं आती मैं तो लोगों की सेवा और खुशहाली की राजनीति करती हूं। चौपालों में गांधी ने ग्राम प्रधानों से ग्राम समाज की पड़ी हुई ख़ाली जमीनों पर आम, जामुन, महुआ, अमरूद आदि फलदार पौधे लगाने के लिए कहा। उन्होंने ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र देते हुए प्रधानों से कहां कि खाली पड़ी जमीनों पर मेंहदी व भीमा बांस लगाएं। प्रधान इससे करोडों की आमदनी कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने ऐसे प्रधानों को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया।

उधर, बीजेपी मुख्यालय पर उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. आरए वर्मा की अध्यक्षता में विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों व विभागों के नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आसन्न विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। कहा कि मैं चाहती हूँ युवा मोर्चा के नौजवान राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रशिक्षण केन्द्र जायस से व अन्य संस्थाओं से स्किल डेवलपमेंट से प्रशिक्षण प्राप्त कर नौकरी व रोजगार पा सकते है। उन्होंने महिला मोर्चा को मेहंदी, मशरूम व मेहंदी की खेती करने का सुझाव तथा किसान मोर्चा को फूलों, काला धान,भीमा बांस व मेहंदी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की। यहां युवा मोर्चा अध्यक्ष चन्दन नारायण सिंह, किसान मोर्चा अध्यक्ष गोविन्द तिवारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष बबिता तिवारी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष डॉ. रामजी गुप्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अजादार हुसैन, महामंत्री डॉबर खां, गांधी सिंह, बाबी सिंह, एसके मिश्रा, राजधर शुक्ला, अरूण द्विवेदी, जेपी सिंह सहित सभी प्रकोष्ठ व विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे।संचालन महामंत्री विजय त्रिपाठी ने किया।

गांधी ने अमऊजासरपुर में पत्रकारों से कहाकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की। कहा कि हिंदुस्तान की सरकार ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है, उन्हें पूरा भरोसा है कि अफगानिस्तान की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हिंदुस्तान की सरकार बड़ा कदम उठाएगी। सांसद मेनका संजय गांधी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में राजनीतिज्ञों व उनक समर्थकों ने बड़े बड़े बंगले बनवाए लेकिन केन्द्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार ने बेघर व गरीब परिवार के लोगों का घर बनाने का काम किया है। पिछले साढ़े चार सालों में 85 हजार मकान बनाए गये। सांसद ने प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत नरेंद्र गिरि के देहावसान पर शोकसंवेदना प्रकट करते हुए दु:ख जताया है। कहा ऐसी घटनाएं बहुत दुखदाई होती हैं। सांसद अमऊजासरपुर से वाया लखनऊ ,आगरा एक्सप्रेस वे होते हुए दिल्ली के रवाना हो गयी। सांसद प्रतिनिधि रणजीत कुमार, जिला उपाध्यक्ष प्रवीन कुमार अग्रवाल, कृपा शंकर मिश्रा,विजय सिंह रघुवंशी, अनिल तिवारी, शशीकांत पांडे, श्याम बहादुर पांडे, कालीसहाय पाठक,राजेश सिंह, राजेश पांडेय, बृजेश वर्मा, प्रभात पांडे, संतोंष दूबे , प्रदीप यादव, राम अभिलाष सिंह,धीरेन्द्र दूबे उपस्थित रहे।

योगी का प्रमोशन कर बनाया जाए पीएम : राकेश टिकैत

लखनऊ, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि भाजपा को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी।

मंगलवार को एक मंथन कार्यक्रम में सवालों का जवाब देते हुए टिकैत ने जहां भाजपा भाजपा को चुनाव में 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने का दावा किया, वहीं यह भी कहा कि भाजपा का हारा हुआ उम्मीदवार भी जीत का प्रमाण पत्र लेकर जाएगा क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तीन नये कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन के एक प्रमुख नेता टिकैत ने इस बात को जोर देकर कहा कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। टिकैत ने पूर्व में भूमि अधिग्रहण कानून के विरूद्ध मुहिम चलाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सराहना भी की।

एक प्रश्न के उत्तर में किसान नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में ही अपने पद से हट जाएंगे और वह राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का प्रमोशन होना चाहिए वह पीएम बन जाएं। उल्लेखनीय है कि अगले वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से भाजपा को 312 और उसे सहयोगी दलों को कुल 13 सीटें मिली थीं।

टिकैत ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर विपक्ष के वोटों में बिखराव का आरोप लगाते हुए कहा कि ओवैसी पैकेज पर हैं और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के वोटों में बिखराव करने आए हैं। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में छह सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को दंगा कराने वाला और बाहरी नेता बताया और किसानों का आह्वान किया था कि इस सरकार (भाजपा) को वोट की चोट दो।

प्रियंका की रैली को लेकर यूपी कांग्रेस के दिग्गजों को टाइमिंट पर आपत्ति

लखनऊ, 21 सितम्बर । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 29 सितंबर से मेरठ में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू करने वाली हैं, ऐसे में पार्टी का एक बड़ा वर्ग रैली के समय पर आपत्ति जता रहा है।

कांग्रेस के एक वयोवृद्ध नेता ने कहा, 'यह 'पितृ पक्ष' अवधि है, जिसे सभी हिंदुओं द्वारा अशुभ माना जाता है, और इस समय चुनाव अभियान शुरू करना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार नहीं है।'

पितृ पक्ष की अवधि 20 सितंबर से शुरू हुई और 6 अक्टूबर को समाप्त होगी।

अधिकांश राजनीतिक दल पितृ पक्ष अवधि के दौरान नए अभियान शुरू करने से बच रहे हैं, हालांकि वे पहले के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रियंका की लिए निर्धारित रैलियां मेरठ (29 सितंबर) से शुरू होंगी, फिर वाराणसी (2 अक्टूबर), आगरा (7 अक्टूबर), गोरखपुर (12 अक्टूबर), आजमगढ़ (17 अक्टूबर) और प्रयागराज (18 अक्टूबर) तक होंगी।

कांग्रेस के एक ब्राहम्ण नेता ने कहा, 'सभी हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि इस अवधि के दौरान कोई नई पहल शुरू नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में, लोग इस पखवाड़े में नए कपड़े भी नहीं खरीदते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन प्रियंका को सलाह दे रहा है या उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि पितृ पक्ष के बाद रैलियां शुरू हों। कुछ दिनों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं।

2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी ने 403 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 39.67 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया।

समाजवादी पार्टी (सपा) को 47 सीटें, बसपा ने 19 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस केवल सात सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी।

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा सोली जे. सोराबजी के नाम पर एंडोमेंट अवार्ड और छात्रवृत्ति की स्थापना

सोनीपत, 21 सितम्बर । भारत के प्रसिद्ध न्यायविद और पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जे. सोराबजी की स्मृति में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने एंडोमेंट अवार्ड और छात्रवृत्ति की स्थापना की है। यह पुरस्कार और छात्रवृत्ति जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में स्नातक कार्यक्रमों में मानवाधिकार कानून और सिद्धांत के क्षेत्र में एक योग्य छात्र को प्रतिवर्ष दिया जायेगा। पुरस्कार की घोषणा हर साल 9 मार्च को श्री सोराबजी की जयंती के अवसर पर की जाएगी। इसमें एक पदक के साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।

सोली सोराबजी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती थे और उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कई ऐतिहासिक मामलों में जिसमें केशवानंद भारती और एस.आर. बोम्मई मामले शामिल थे, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का बचाव किया था। इसलिए छात्रवृत्ति और पुरस्कार सोली सोराबजी की उपलब्धियों और मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनके योगदान की याद दिलाता है।

सोली जे. सोराबजी एंडोमेंट अवार्ड और छात्रवृत्ति वरिष्ठ अधिवक्ता सात्विक वर्मा द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता के कारण स्थापित की गई है। एंडोमेंट बनाते समय श्री वर्मा ने कहा कि माननीय सोराबजी का जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी। इन वर्षों में मैंने उनके साथ एक बहुत करीबी व्यक्तिगत संबंध बनाये थे, जिससे एक वकील के रूप में उनके व्यक्तिगत पक्ष को जानने में मुझे बहुत मदद मिली। मैंने महसूस किया कि मानवाधिकारों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को जारी रखने का सबसे अच्छा तरीका उनकी स्मृति में एक विस्तारित छात्रवृत्ति और पुरस्कार की स्थापना करना था।

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर डॉ. सी.राज कुमार ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा , 'श्री सोली जे सोराबजी के नाम पर यह पुरस्कार स्थापित करने और इसे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ साझा करने के लिए हम श्री सात्विक वर्मा के आभारी हैं। कानून के छात्रों के पोषण और भारत के अग्रणी कानूनी दिग्गजों में से एक के नाम और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम श्री वर्मा का धन्यवाद करते हैं।'

इस पुरस्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रोफेसर डाबीरू श्रीधर पटनायक, रजिस्ट्रार, जेजीयू ने कहा, एक शोध गहन विश्वविद्यालय के रूप में और ओपीजिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में स्नातक विशेषताओं के परिणाम के रूप में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे छात्र सामाजिक और सीखने की क्षमता विकसित करेंगे।'

सोली जे. सोराबजी का जन्म 1930 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई में अध्ययन किया और 1953 में बार में भर्ती हुए। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में उन्हें रोमन लॉ एंड ज्यूरिस्प्रुडेंस (1952) में किनलोच फोर्ब्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 द्वारा भारत के नंबर एक लॉ स्कूल और दुनिया के 76 वें रैंक वाले लॉ स्कूल का स्थान दिया गया है। सोली जे सोराबजी अवार्ड से यहाँ के छात्रों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।

महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने रेलवे संरचनाओं का किया निरीक्षण

मालीगांव, 31 सितम्बर । पूर्वोत्तर सीमा रेल के महाप्रबंधक, श्री अंशुल गुप्ता ने 20 सितंबर, 2021 को कामाख्या, गुवाहाटी और न्यू गुवाहाटी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने अपने निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधा, साधन, सुरक्षा, चल रहे विकास कार्यों और माल ढुलाई सुविधाओं के विभिन्न मुख्य मापदंडों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उनके साथ मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, लामडिंग मंडल के मंडल रेल प्रबंधक और अन्य मंडल अधिकारी मौजूद थे।

महाप्रबंधक ने कामाख्या और गुवाहाटी रेलवे स्टेशनों पर चल रहे स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर सीमा रेल अपने सभी परिसरों अर्थात स्टेशनों, ट्रेनों, कार्यालयों, कॉलोनियों, कार्यशालाओं, रखरखाव डिपो, अस्पतालों आदि में स्वच्छता में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 16 से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है।

कामाख्या और गुवाहाटी रेलवे स्टेशनों के अपने दौरे के दौरान, महाप्रबंधक ने यात्री सुविधाओं और सिक लाइन, कोचिंग डिपो के विकास कार्यों की प्रगति और ट्रेन परिचालन में लचीलापन और दक्षता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लाइनों के प्रावधान की समीक्षा की। फूड स्टॉल, सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम, टिकट काउंटर सहित यात्री सुविधाओं से संबंधित अन्य कार्यों का निरीक्षण किया गया। महाप्रबंधक ने स्टेशनों पर यात्रियों से बातचीत भी की। बाद में उन्होंने गुवाहाटी में कोचिंग डिपो का निरीक्षण किया और मेंटेनेंस कर्मियों, विशेष रूप से ट्रेन मेंटेनेंस कार्यों में लगी महिला कर्मियों के साथ बातचीत की।

गुवाहाटी कोचिंग डिपो और स्टेशन पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ चर्चा की गई और महाप्रबंधक ने कार्य प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कोचिंग, पार्सल और कोचिंग के अलावा अन्य आय बढ़ाने का भी सुझाव दिया। न्यू गुवाहाटी स्टेशन पर माल और पार्सल हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार के लिए चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया गया।

अशोक गहलोत की जगह लेंगे सचिन पायलट? पंजाब के बाद कांग्रेस ने राजस्थान का भी ब्लू प्रिंट किया तैयार

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। पंजाब के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बदलाव लगभग तय है। पांच राज्यों से विधानसभा चुनाव के बाद इन राज्यों की कमान नए मुख्यमंत्रियों को मिल सकती है। इसके लिए कांग्रेस पूरा खाका तैयार कर चुकी है।

पार्टी नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस नेताओं के सपंर्क में है। पार्टी को सिर्फ उपयुक्त समय का इंतजार है।

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस हाईकमान अपना रुतबा साबित करने में सफल रही है। इस बदलाव के जरिए पार्टी नेतृत्व यह संदेश देने में सफल रही है कि विधायक मुख्यमंत्री के बजाए उसके कहने पर अपना नेता तय करेंगे।

पार्टी इस बदलाव को पीढ़ी परिवर्तन के तौर पर देख रही है। कांग्रेस ने करीब 80 साल के कैप्टन को हटाकर उनकी जगह 58 साल के चन्नी को मौका दिया है। राजस्थान में भी पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी 70 साल के गहलोत की जगह 44 साल के सचिन पायलट पर दांव लगाना चाहती है।

यही वजह है कि शुक्रवार को कैप्टन का इस्तीफा लेने के बाद सचिन पायलट को दिल्ली तबल किया गया। उनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लंबी बात हुई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राजस्थान में बदलाव का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर पायलट के भरोसेमंद विधायकों को शामिल करेंगे। पर मुख्यमंत्री पद में बदलाव पांच राज्यों के चुनाव के बाद होगा।

प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राजस्थान में मुकाबला भाजपा से है। ऐसे में वर्ष 2024 का चुनाव जीतने के लिए विधानसभा जीतना बेहद जरूरी है। क्योंकि, 2018 में सरकार बनाने के बावजूद पार्टी 2019 के लोकसभा में सभी 25 सीट हार गई थी।

ऐसे में पार्टी को कम से कम एक-डेढ़ साल पहले राजस्थान में बदलाव करना होगा। पायलट काफी समय से मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हर बार विधायकों में कम समर्थन के चलते बात टल जाती थी। पर पंजाब में कांग्रेस ने इस फार्मूले को बदल दिया है। ऐसे में राजस्थान में बदलाव लगभग तय है।

सरकारी योजनाओं .....

शुरुआत मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रदर्शनी स्टालों के उद्घाटन के साथ हुई। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्ज्वलित किया। कार्यक्रम में निदेशक (एमएसएमई) एम रविकुमार ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने के प्रयासों को बढ़ावा देना था।

मुख्य अतिथि कादो छिरिंग नमका ने अपने संबोधन में स्वयं सहायता समूहों को अपने स्टालों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए धन्यवाद और बधाई दी। उन्होंने उन विभिन्न समस्याओं के बारे में बात की जो एक इच्छुक और उद्यमी को अपना प्रयास शुरू करते समय सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह उनके और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से काम करने और इच्छुक लोगों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने का आग्रह किया और उनसे नियमित आधार पर कार्यक्रम और प्रशिक्षण आयोजित करने का आग्रह किया।

विशिष्ट अतिथि मन बहादुर छेत्री ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के विकास में मदद करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को आगे आने और सरकार द्वारा प्रदान की गई योजनाओं का लाभ उठाने और सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। इसी तरह सचिव शर्मा ने दस उद्यमियों को चुनने और उन्हें दो साल के भीतर निर्यातक बनने के लिए प्रशिक्षण देने के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न नकदी फसलों का भी उल्लेख किया, जिन्हें जिलेवार सौंपा गया है, जैसे कि अदरक (दक्षिण), डल्ले (पूर्व), इलायची (उत्तर) और सब्जियों की खेती (पश्चिम)। अमित शर्मा (डीजीएफटी) ने राज्य के विकास में निर्यात के महत्व के बारे में संक्षेप में बात की और जैविक उत्पादों के निर्यातक के रूप में राज्य की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करके विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

सीएम की कार्यशैली .....

पर हमला होने का भी आरोप लगाया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तामलिग ने कहा है कि सिक्किम के आम लोगों से लेकर खुद चामलिंग को पता है कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों को पीटा गया, कितने मारे गए। एसकेएम सरकार के गठन के बाद राज्य में हत्या, हिंसा, दंगे और तोड़फोड़ का सिलसिला बंद हो गया है। सेवा ही धर्म है के नारे के साथ काम करने वाली एसकेएम सरकार पर आरोप लगाना पवन चामलिंग के मानसिक दिवालियेपन के अलावा और कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री लगातार असहाय, गरीब और बीमार लोगों को सम्मान के साथ मिंतोकगांग बुला रहे हैं और उनकी समस्याओं और कमियों को दूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी पहल पर गरीब मरीजों के इलाज पर 10-12 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। उन्होंने चामलिंग पर दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर गोली चलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में चामलिंग सरकार का विरोध नहीं कर सकते है। क्योंकि मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में एसडीएफ पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। एसकेएम पार्टी नशा उन्मूलन के उद्देश्य से सारथी नामक संगठन बनाकर सिक्किम में नशीली दवाओं के खिलाफ कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने पवन चामलिंग को कमरे में बैठकर और वास्तविकता को जाने बिना, बिना कुछ देखे, सरकार की उपलब्धियों के बारे में अनर्गल आरोप न लगाने का सुझाव दिया है।

क्षेत्रीय आयुर्वेद ....

एवं आसन को अपनाने का आह्वान किया

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपास्थित डॉ. देवव्रत पुरोहित, प्राचार्य ने आयुर्वेद के गौरवशाली इतिहास को याद कराते हुए पेड़-पौधों के औषधीय गुणों पर प्रकाश डाला साथ ही उन्होंने उत्तम स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद अपनाने की सलाह दी सम्मानित अतिथि श्रीमती डोमा लाह्यु झिम्वा, प्रशासमीय अधिकारी ने भी विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों के महत्व को रेखांकित करते हुए लोगों से सुपोषण के लिए आयुर्वेद अपनाने की सलाह दी

कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ. विनुधा ने आहार के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा करने के साथ साथ योग एवं आसनों के मानव शरीर एवं मन पर होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों को पॉवर ख्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुत किया और विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन किया एवं अभ्यास भी कराया उक्त अवसर पर काउंसलर मिलन गौतम उपस्थित थे।

कार्यक्रम में प्रोटीनयुक्त पौष्टिक आहार अतिथियों को प्रदान किया गया और मुख्य अतिथि जीटी ढुंगेल द्वारा उपस्थित सभी छात्राओं एवं जनसमूह को उक्त प्रोटीन युक्त आहर वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के बाद एससीएसपी, परियोजना के तहत स्वास्थ्य परीक्षण एवं नि:शुल्क दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अशोक कुमार सिन्हा, अनुसंधान अधिकारी ने किया। जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. राहुल धनराज घुसे, अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया गया।

आप असली है, बीजेपी नीतियों की नकल कर रही है : केजरीवाल

पणजी, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। आम आदमी पार्टी सरकार के योजनाओं की नकल करने का आरोप लगाते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोगों को भाजपा के बजाय 'ओरिजनल' आप को चुनना चाहिए, जो केवल अपनी नीतियों की नकल करती है।

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है।

केजरीवाल ने उत्तरी गोवा के मापुसा शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में पानी मुफ्त मिलेगा। मैं बहुत खुश था। हमने इसे चार साल पहले दिल्ली में किया था। मैंने सुना है कि उन्होंने सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू कर दी है। हमने इसे तीन साल पहले दिल्ली में शुरू किया था।'

केजरीवाल ने कहा, 'मेरा मानना है कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है, वह (सावंत) गोवा में उनकी नकल कर रहे हैं। जब असली मौजूद है, तो आपको डुप्लिकेट की आवश्यकता क्यों है? जब गोवा के लोग ओरिजनल के लिए वोट कर सकते हैं, तो आपको डुप्लिकेट की आवश्यकता क्यों है। डुप्लीकेट व्यक्ति 'गड़बड़' (भ्रम) करेगा।'

गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के बीच पिछले कुछ महीनों में राज्य विधानसभा चुनावों से पहले जुबानी जंग और चुनाव से पहले घोषणाओं में लगे हुए हैं।

आप द्वारा राज्य में घरेलू घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा के बाद, भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने हर घर में 16,000 लीटर मुफ्त पानी देने की घोषणा की है।

आप ने मंगलवार को डोमिसाइल वाले गोवावासियों के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण का भी वादा किया और बेरोजगार युवाओं और परिवारों को 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की राशि आवंटित करने का भी वादा किया है।

गुजरात तट ड्रग्स तस्करी का पसंदीदा रास्ता क्यों? कांग्रेस का सवाल

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस ने मंगलवार को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर करीब 15000 करोड़ रुपए कीमत की करीब 3,000 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। हेरोइन की जब्ती पर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर कैसे सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नाक के नीचे इस तरह का ड्रग सिंडिकेट चल रहा है।

बता दें कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा बंदरगाह पर दो कंटेनरों से 15,000 करोड़ रुपए मूल्य की 2,988.21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और बाद में चेन्नई से एक आयात फर्म चलाने वाले एक जोड़े को गिरफ्तार किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार से यह भी सवाल किया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्णकालिक प्रमुख का पद 18 महीने से खाली क्यों है? खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जो गुजरात से हैं, इस ड्रग सिंडिकेट को तोड़ने में असमर्थ क्यों हैं?

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में भारत में मादक पदार्थों की तस्करी में काफी वृद्धि हुई है और यह पिछले कुछ सालों से चल रहा है। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि यह न केवल भारत के युवाओं के वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर सकता है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण के लिए संभावित वित्त पोषण का मार्ग है। खेड़ा ने दावा किया कि मुंद्रा पोर्ट से लगभग तीन टन हेरोइन की जब्ती न केवल भारत में, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी अवैध दवाओं में से एक है।

खेड़ा ने दावा किया कि जब्त ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 21000 करोड़ रुपए है। कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया है कि इतनी बड़ी मात्रा ड्रग्स पोर्ट पर कैसे पहुंचा, सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या कर रहा था? खेड़ा ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में गुजरात तट पाकिस्तान, ईरान या अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सबसे पसंदीदा मार्ग बन गया है। ड्रग्स की जब्ती को लेकर खेड़ा ने सरकार से कई सवाल भी किए। खेड़ा ने पूछा कि क्या ड्रग्स की 10 खेपों को जाने दिया जा रहा है और एक पकड़ लिया जा रहा है ताकि लोगों को यह पता चल सके एजेंसियां काम कर रही है।

उधर मुंद्रा पोर्ट ने मामले में अपना पक्ष रखा है। इसमें मुंद्रा पोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 16 सितंबर 2021 को, डीआरआई और सीमा शुल्क के एक संयुक्त अभियान ने मुंद्रा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचे अफगानिस्तान से दो कंटेनरों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित हेरोइन का पता लगाया। हम अवैध ड्रग्स को जब्त करने और आरोपी को पकड़ने के लिए डीआरआई और सीमा शुल्क टीमों को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। मुंद्रा पोर्ट ने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि यह बयान अदाणी समूह के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार पर विराम लगा देगा।

कोलकाता और दक्षिण बंगाल में हो रही लगातार बारिश, शहर के अधिकांश हिस्से जलमग्न

कोलकाता, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। हाई टाइड की स्थिति के साथ लगातार बारिश ने शहर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण बंगाल के प्रमुख क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया है। मौसम विभाग ने स्थिति को और खराब बताते हुए बुधवार को कोलकाता और दक्षिण बंगाल के कई जिलों में और बारिश होने की संभावना जताई है।

पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश से शहर के अधिकांश हिस्सों में पानी भर गया है। बेहाला, मोमिनपुर, एकबलपुर, खिद्दरपुर, कालीघाट समेत शहर के दक्षिणी हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। एसएसकेएम, एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जैसे प्रमुख सरकारी अस्पतालों में पानी घुस गया। कई वाडरें के अंदर पानी है जिससे मरीजों, डॉक्टरों और नर्सों को परेशानी हो रही है।

पानी नेताजी सुभाष अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में भी घुस गया, जिससे उड़ान सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई। हवाई अड्डा अधिकारियों के मुताबिक, जिन 13 विमानों ने उड़ान भरी थी, उन्हें रनवे पर पानी की वजह से 45 मिनट से 2 घंटे तक की देरी हुई। इसके अलावा, रनवे पर पानी के कारण छह विमानों को नहीं उतारा जा सका क्योंकि वे उतर नहीं सके।

वहीं उल्टाडांगा, मानिकतला, बेलगछिया के कई इलाके घुटनों तक पानी में डूबे हुए हैं। भारी बारिश ने शहर को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया और शहर के कई इलाकों, खासकर मध्य और दक्षिण कोलकाता के इलाकों में पानी भर गया है। बेहाला, एमजी रोड, पार्क सर्कस, पार्क स्ट्रीट, थिएटर रोड, शेक्सपियर सरानी जैसे इलाके घुटनों तक पानी में डूबे हुए है। लोगों को अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने के लिए पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बना चक्रवाती तूफान धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अब यह जमीन से 5.8 किमी ऊपर तक फैला हुआ है। इसी समय, मौसमी अक्ष गोवा से कोलकाता तक दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व तक फैली हुई है। नतीजतन, मंगलवार को भी राज्य भर में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी है।

विभाग के अनुसार मंगलवार को बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना में भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कई चेतावनियां जारी की हैं। मूसलाधार बारिश से खेत में सब्जियों और फसलों को नुकसान होने की संभावना है।

लगातार बारिश के कारण पूर्वी मिदनापुर जिले के पताशपुर, भगवानपुर और एगरा विधानसभा क्षेत्रों के कई गांव और कांथी उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। जिले भर में दो लाख से अधिक परिवार जलमग्न हो गए हैं।

पूर्वी मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट पूर्णेंदु मांझी ने कहा कि लगभग 80,000 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रशासन ने उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराया है।

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 08:00 PM

DEAR PARROT EVENING

Draw No:143 DrawDate on:21/09/21

1st Prize ₹1 Crore/- 73G 74385

Cons. Prize Rs.1000/- 74385 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

14042 25628 32243 44329 63142 63888 74719 74721 76686 86375

3rd Prize ₹450/-

1290 1393 1972 2083 3055 4334 4520 6228 6769 7353

4th Prize ₹250/-

1325 1896 3009 3106 4215 6092 6862 8760 8782 8886

5th Prize ₹120/-

0067 0385 0443 0571 0584 0746 0859 0941 1036 1112
1323 1558 1697 1709 1864 2048 2062 2071 2096 2102
2142 2337 2363 2442 2476 2602 2934 2984 3080 3269
3312 3721 3909 4114 4231 4818 4923 4959 4987 5064
5071 5078 5139 5249 5590 5616 5645 5702 5848 5933
6035 6048 6174 6307 6695 6752 6813 6880 6996 7014
7086 7125 7132 7168 7228 7238 7314 7440 7474 7542
7556 7570 7591 7806 7853 7893 8024 8034 8068 8076
8320 8410 8683 8754 8809 8888 8999 9037 9083 9212
9282 9300 9353 9385 9440 9620 9625 9752 9876 9897

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 07:00 PM

DEAR MOON TUESDAY

Draw No:43 DrawDate on:21/09/21

1st Prize ₹1 Crore/- 99H 72778

Cons. Prize Rs.1000/- 72778 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

12738 13711 19987 27789 39514 42163 50320 67027 72497 96942

3rd Prize ₹450/-

0195 0622 1385 1478 1906 4128 7762 8018 9083 9665

4th Prize ₹250/-

1030 1865 2657 3207 6020 6393 6900 7754 8031 8334

5th Prize ₹120/-

0034 0295 0362 0478 0547 0592 0664 0749 0832 0875
1071 1077 1127 1130 1265 1480 1501 1749 1801 1807
1809 1898 2035 2130 2232 2354 2458 2560 3019 3096
3161 3218 3236 3282 3358 3382 3385 3532 3608 3672
3676 3812 3902 3937 4005 4006 4037 4080 4406 4514
4781 4900 5067 5087 5142 5161 5299 5434 5610 5639
5688 5819 5868 5919 5958 6039 6186 6257 6363 6608
6673 6683 6686 6786 6937 7039 7477 7567 7654 7776
7808 8044 8144 8377 8450 8540 8866 8878 9094 9153
9186 9240 9333 9350 9411 9456 9506 9650 9704 9965

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 02:00 PM

DEAR TEESTA MORNING

Draw No:43 DrawDate on:21/09/21

1st Prize ₹1 Crore/- 81J 83031

Cons. Prize Rs.1000/- 83031 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

02097 12539 16937 30607 48529 54813 57852 76490 79612 80150

3rd Prize ₹450/-

0721 2508 2786 3785 3875 6487 6646 7401 8792 8893

4th Prize ₹250/-

0430 0794 2056 2237 2825 3356 4963 5072 8747 8765

5th Prize ₹120/-

0053 0138 0161 0353 0444 0468 0580 0616 0675 1026
1062 1065 1076 1139 1143 1250 1394 1621 1745 1977
1982 2111 2226 2278 2298 2451 2487 2715 2717 2849
2875 3054 3159 3505 3582 3672 3817 4067 4249 4301
4484 4652 4862 5003 5020 5134 5188 5211 5237 5334
5352 5403 5493 5539 5552 5583 5663 5729 5755 5824
5849 5910 5972 6010 6232 6272 6735 6859 7019 7054
7061 7201 7367 7383 7402 7867 8021 8079 8159 8358
8379 8407 8442 8587 8617 8966 9001 9022 9042 9086
9143 9244 9497 9797 9858 9969 9973 9980 9990 9996

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

OFFICE OF THE MISSION DIRECTOR

NATIONAL HEALTH MISSION

H & FW DEPARTMENT

GOVERNMENT OF SIKKIM

No. 2079/H & FW/NHM/21-22 Dated : 21/09/2021

EMPLOYMENT NOTICE

The National Health Mission, State Health Society, Sikkim, invites application for the walk-in-Interview from the eligible local candidates having SSC/CoI issued by the competent authority to fill up to following positions (till 31st March 2022) under ECRP-II package at the office of JD/HR& NO/NHM.

Last date of submission of application: 27th September 2021.

Sl No.	Name of the post	No. of posts	Essential Qualification	Desirable	Monthly salary
1	Hub Coordinators	05	1. Bachelor of Technology in computer sciences/electronic and telecommunication from the recognized university OR 2. Masters in Computer Applications (MCA) from recognized university	Master's in Business Administration (MBA) and experience in field related to Telemedicine for one year	₹ 35,000/- per month + incentive as per the remoteness of location (max 10,000)
2	Telemedicine Administrators	11	Bachelors in Computer Application from a recognized university		₹ 15,000/- per month + incentive as per the remoteness of location (max 5,000)
3	MO (telemedicine)	04	MBBS from recognized university with MCI registration		₹ 55,000/- per month + incentive as per the remoteness of location (max 20,000)

Dr. Madan Mani Dhakal, MD
JD/HR & NO/NHM
National Health Mission

R.O. No.: 215/IPR/PUB/Classi/2122, DT.: 21.09.2021

संपादकीय पृष्ठ

पंजाब में बदलाव

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से बमुश्किल छह महीने पहले नेतृत्व परिवर्तन न केवल चौंकाता है, बल्कि एक खास तरह के राजनीतिक चरित्र को भी सामने रखता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर नेता, जिन्होंने भाजपा के विजय रथ को कम से कम पंजाब में थामे रखा था और जो कांग्रेस को गौरव के कुछ पल नसीब कराते थे, वह अचानक अप्रिय कैसे हो गए? चार साल उन पर कांग्रेस को पूरा विश्वास रहा और जब उनका कार्यकाल अंतिम छमाही में पहुंचा, तो उन्हें पद से विदा करने का इंतजाम कर दिया गया। क्या पंजाब में सत्ता परिवर्तन केवल चुनावी हार के डर की वजह से हुआ है? काश! हार का यह भय हमारी राजनीतिक पार्टियों को हर दिन सताता, तो चुनाव की दहलीज पर पहुंचकर नेतृत्व परिवर्तन की जल्दी नहीं मचती। पंजाब में फिर दिख गया कि सत्तासेवी राजनीति अपने स्वभाव में कितनी निर्मम होती है। कल तक कैप्टन कांग्रेस के लिए नायक हुआ करते थे और आज चरणजीत सिंह चन्नी से उम्मीदें हैं। सत्तासेवी राजनीति न तो कैप्टन के प्रति उदार थी और न चन्नी पर अनायास मेहरबान हो जाएगी।

सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही चरणजीत सिंह चन्नी पुरजोर ढंग से सक्रिय हो गए, क्योंकि उनके पास समय कम है। बमुश्किल चार महीनों में वे तमाम काम करने हैं, जो अमरिंदर सिंह अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए। उन्होंने सत्ता संभालते ही किसानों को लुभाने का प्रयास सबसे पहले किया है। केंद्र सरकार से तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहरा दी है। पंजाब में चुनाव जीतने के लिए किसानों को खुश रखना सबसे जरूरी है, यह काम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने ढंग से कर रहे थे, लेकिन इस मोर्चे पर उनकी लोकप्रियता पिछले महीनों में कम हुई थी। यह भाव किसानों में आने लगा था कि कैप्टन किसानों की मांग से किसी तरह से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि कैप्टन के किन कामों को कांग्रेस गलत मानती है या बदलती है। चन्नी ने बता दिया है कि उन्हें हाईकमान की ओर से 18 मुद्दों की सूची मिली है, जिन्हें वह अपने बाकी कार्यकाल में ही पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री बनते ही चन्नी ने राज्य में किसानों के बकाया पानी व बिजली बिल माफ करने का बड़ा एलान किया है, लेकिन क्या यही काम कुछ पहले कांग्रेस कैप्टन से नहीं करा सकती थी? बहरहाल, कांग्रेस हाईकमान को बदलाव के अपने फैसले का सम्मान रखने के लिए बहुत कुछ करना होगा। बड़बोलापन आज की राजनीति का अहम हिस्सा है। चन्नी ने भी कुछ आकर्षक संवाद कहे हैं, जैसे किसान डूबा, तो देश डूबेगा, किसान पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगर किसानों पर आंच आई, तो गर्दन पेश कर दूंगा। ऐसी ही भाषा के लिए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को भी जाना जाता है, लेकिन क्या ऐसी भाषा के बल पर सरकार चलाते हुए चुनाव में जीत हासिल हो सकती है?

बेशक, उपलब्ध विकल्पों के बीच से कांग्रेस का यह चयन प्रशंसनीय है और राजनीतिक रूप से विपक्षी दलों में पैदा बेचैनी साफ संकेत कर रही है कि तीर निशाने की ओर गया है। यह तीर तभी निशाने पर लगेगा और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार तभी बची रह पाएगी, जब पार्टी के दिग्गज नेता एक-दूसरे की टांग पर फोकस करने के बजाय कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।

कितने सच बोलते हैं आंकड़े

विभूति नारायण राय

आंकड़ों के बारे में आम सहमति है कि वे हमेशा या पूरा सच नहीं बोलते और उनमें तैयार करने वालों की व्यक्तिगत पसंद-नापसंद की झलक हमेशा दिखती रहती है। पर यह भी सच है कि आंकड़ों का कोई विकल्प नहीं है, खासतौर से भारत जैसे एक वैविध्यपूर्ण समाज में, जहां नीति-निर्धारकों के पास धर्मों, जातियों, भाषाओं और भिन्न राष्ट्रीयताओं में बंटे समाजों के लिए योजनाएं बनाते समय इनके अलावा कोई दूसरा बेहतर आधार न हो।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2020 की रिपोर्ट छपकर आ गई है। देश के विभिन्न राज्यों में अपराधों की स्थिति समझने के वास्ते किसी भी जिज्ञासु शोधार्थी के लिए ब्यूरो की रिपोर्टें एक प्रस्थान बिंदु की तरह होती हैं। यह याद रखने की जरूरत है कि 1986 में स्थापित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का काम सिर्फ राज्यों से प्राप्त अपराधों के आंकडे. संकलित कर प्रकाशित कर देना है। उसमें इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि इनका समाजशास्त्रीय अध्ययन कर वह अपराधों के घटने या बढ़ने की प्रवृत्तियों की शिनाख्त कर सके। इस काम को तो दूसरे शोध संस्थानों को ही करना होगा और निश्चित रूप से ब्यूरो के संकलित आंकड़े उनके लिए बहुमूल्य सिद्ध होते हैं। आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते समय यह जरूर याद रखना होगा कि सभी राज्य सरकारों की तरफ से कोशिश होती है कि अपराध को कम करके दिखाया जाए। अपवाद-स्वरूप भी ऐसा राज्य तलाशना मुश्किल होगा, जो इन आंकड़ों के स्रोत पुलिस थानों में शत-प्रतिशत आपराधिक मामले दर्ज कराने पर जोर देते हों। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो सर्वविदित है कि आधे से भी कम मामलों में एफआईआर दर्ज होती हैं।

बहरहाल, ब्यूरो की यह रिपोर्ट वर्ष 2020 की है, जब कोविड महामारी के चलते देश का अधिकांश हिस्सा बंद था। सड़कों पर कम लोग निकलते थे और ज्यादातर कारखानों, दफ्तरों या शिक्षा संस्थानों में ताले लटके हुए थे। ऐसे में, यह स्वाभाविक ही है कि घरों के बाहर होने वाले अपराधों में गिरावट आई और चारदीवारियों के भीतर घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी होंगी। अवसादजन्य हिंसा या आत्महत्याओं में भी वृद्धि हुई ही होगी, पर लीक से हटकर सोचने की बौद्धिक सलाहियत से वंचित ब्यूरो ने अपराध के पारंपरिक खानों में इनके लिए गुंजाइश नहीं रखी है, इसलिए उन पर बातचीत नहीं हो सकती। इसके बावजूद इस रिपोर्ट से समकालीन समाज को समझने में मदद मिलेगी।

कोविड महामारी और परिणामस्वरूप लॉकडाउन के चलते महिलाओं, बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों में कमी आई है, ऐसा ब्यूरो का मानना है, पर यह अन्य समाजशास्त्रीय स्रोतों के निष्कर्षों से भिन्न है। तमाम विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के जमीनी अध्ययन बताते हैं कि बडे. पैमाने पर रोजगार जाने, आमदनी में कटौती और जीवन में तरह-तरह की अनिश्चितताओं से उत्पन्न तनाव ने मध्य आयु वर्ग के सदस्यों का जीवन एक खास तरह के अवसाद से भर दिया है और यह घरेलू हिंसा के रूप में प्रकट हुआ है। बहुत से सर्वेक्षणों और अध्ययनों ने इसकी पुष्टि की है। ऐसे में, ब्यूरो के आंकडे. चौंकाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे विश्वसनीय हैं। इसी तरह से शिक्षा संस्थानों की बंदी के चलते घरों में कैद बच्चे भी चिड़चिड़े हुए हैं और उनके व्यवहार में भी रेखांकित किया जा सकने वाला परिवर्तन आया होगा, जिनको पकड़ने में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकडे. मदद नहीं करते। हालांकि, यह समझ में आता है कि चोरी, सेंधमारी, राहजनी और डकैती जैसे मामलों में कोविड-काल में कमी आई है।

अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों के मामलों में 9.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों द्वारा दर्ज मुकदमों में 9.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह समझ आने वाली स्थिति है, क्योंकि कोविड के लॉकडाउन से अमूमन ग्रामीण भारत, जहां अधिकतर अनुसूचित जातियां या जंगलों के नजदीकी रिहायशी इलाके, जहां अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, अप्रभावित रहे। इन इलाकों में जीवन चलता रहा, इसलिए इतनी वृद्धि सामान्य कही जाएगी।

लेकिन इन आंकड़ों में दो क्षेत्र दिलचस्प हैं। इस दौरान सरकारी आदेशों के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई। यह स्वाभाविक ही है कि कोविड-काल के निर्देशों, यथा मास्क पहनने या सामाजिक दूरी बनाए रखने के आदेश का अनुपालन करना भारतीय जन के लिए सांस्कृतिक आघात की तरह था और इस संबंध में बड़ी संख्या में मुकदमे कायम हुए। दूसरा क्षेत्र भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जहां अपराध कम हुए बताए गए। यह कैसे हुआ? नागरिकों के सामान्य संपर्क में आने वाले सरकारी कार्यालय आमतौर से बंद रहे, इसलिए स्वाभाविक रूप से संपर्क में कम नागरिक आए, और परिणामस्वरूप उनके उत्पीड़न की घटनाएं भी कम हुईं, लेकिन उस एक क्षेत्र का क्या हुआ, जिसका एक बड़ी आबादी से महामारी के दौरान पाला पड़ा। यह क्षेत्र था स्वास्थ्य।

अमूमन आम दिनों में आबादी के छोटे हिस्से से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का संपर्क होता है और उनका अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन इस बार तो महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ा और बड़े पैमाने पर उन्हें ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ा, जो प्रचलित कानूनों के अंतर्गत भी भ्रष्टाचार की परिधि में आते हैं और इन मामलों में मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। देश भर के अखबार ऐसी खबरों से भरे पड़े थे, जिनमें मरीजों या तीमारदारों के साथ दुर्व्यवहार, दवाओं और अन्य सुविधाओं के लिए अवैध उगाही या फिर सरकारी तंत्र की अक्षमता के किस्से बयान किए गए थे।

महामारी के दौरान जनता को मिले तल्ख अनुभवों पर गीत रचे गए, कहानियां लिखी गईं, फिल्में बनीं और इन सबके बावजूद ब्यूरो की रिपोर्ट अगर भ्रष्टाचार के मामले कम दिखा रही है, तो स्पष्ट है कि इसे गहराई से परखने की जरूरत है।

पूरी संभावना है कि बहुत कम प्रकरण थानों में लिखे गए। यह भी संभव है कि बहुत से मामलों में पीड़ित पुलिस के पास न गए हों। लोगों को उम्मीद नहीं रहती कि उनकी शिकायतें दर्ज होंगी या वे सरकारी मशीनरी से ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद करते हों और जब तक कोई बड़ी दुर्घटना न घटे, वे थाना-कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। कुछ भी हो, भ्रष्टाचार के मामलों में गिरावट हमारी सामाजिक संरचना पर एक टिप्पणी की तरह तो है ही।

विश्व शांति का अर्ध सत्य

वीर सिंह

विश्व शांति की अवधारणा, इच्छा और उस स्थिति को स्थापित करने के प्रयास सुखद अनुभूति देते हैं। विश्व शांति सदैव मानव की एक ऐसी आदर्श स्थिति की मनोकामना है, जिसमें वह अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता, रचनात्मकता और प्रफुल्लता के साथ जीवन यापन कर सके। विश्व शांति एक विचार है, जिसमें समाहित हैं अहिंसा, सभी देशों में आपसी सहयोग, दुनिया के सभी लोगों का सम्मान और सभी को जीवन की मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति।

विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, दर्शनों और विचारों की आदर्श राज्य निर्माण की अलग-अलग अवधारणाएं हो सकती हैं, लेकिन शांति का मार्ग वही है, जो मानव को उसकी गहरी मानवीयता का भान कराए। मानव अधिकारों, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, चिकित्सा अथवा कूटनीति को संबोधित करके विश्व शांति स्थापित करने का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से घोषित है। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्ध अथवा युद्ध की घोषणा के बिना देशों के आपसी संघर्षों को हल करने के उद्देश्य को स्पष्ट किया।

लेकिन तब से सैकड़ों हजारों युद्ध दुनिया में हो चुके हैं, लाखों लोगों का खून बह चुका है। हमारे आधुनिक काल में तो युद्ध विराम ही विश्व शांति का संकेतक बन गया है। किन्हीं दो देशों में जब तक तनाव भीषण युद्ध में परिवर्तित न हो जाए, तब तक यह माना जाता है कि 'शांति की स्थिति' बनी हुई है। दूसरे शब्दों में कहें, तो शांति का अर्थ बहुत संकीर्ण कर दिया गया है। विश्व शांति के मुद्दे बड़े लचकदार हैं। शांति का अभी कोई दर्शन शास्त्र सृजित नहीं हुआ है।

जिंदगी का एक इतना महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक उलटबांसियों और युद्ध के कुरुक्षेत्रों में फंसा है। देशों, धर्मों और विचारों में भले ही ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य के ज्वालामुखी फटते रहें, सीमा पर लड़ाई जारी नहीं, तो शांति ही शांति! बिना रक्तपात के तख्ता पलट दिया गया तो शांति! तालिबान ने भी बिना युद्ध के सत्ता प्राप्त कर ली, वह भी स्थिति का लाभ उठाने वालों के लिए 'शांति' का एक उदाहरण! आतंकवाद भी विश्व शांति का कदाचित ही उल्लंघन माना जाता है।

भयानक गरीबी, कुपोषण, भुखमरी, हत्याएं, बलात्कार, मानवाधिकारों का हनन आदि भी शायद ही शांति उल्लंघन के सूचक माने जाते हैं। और वनों का विनाश, वन्यजीवों की हत्याएं, पालतू पशुओं को भोजन, दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए हत्या तो शांति की परिधि में ही रखा जाता है। यह अपरिभाषित शांति, शांति का अर्ध सत्य है, जो अशांति से भी अधिक भयावह है।

विश्व शांति की अवधारणा में निहित एक अधकचरा पहलू यह भी है कि इस पर मात्र मानव जाति का ही अधिकार है। मानव की, मानव के लिए, मानव द्वारा शांति। पृथ्वी के सभी अन्य प्राणियों को भी शांति की इतनी ही आवश्यकता है, जितनी मानव को। धरती पर लगभग 85 लाख जीवों में मानव एक है, और केवल एक की शांति के लिए अन्य सभी को 'शांतिपूर्ण दुनिया' में सब दुख-संकट झेलने के लिए छोड़ दिया जाए, यह घोर अनैतिक है!

शांति की बातों में और शांति स्थापित करने के प्रयासों और प्रक्रियाओं में नैतिकता के मानदंड गधे के सिर से सींग की तरह लुप्त हैं। युद्ध विराम हो जाए, शांति की प्रक्रिया पूर्ण! इस प्रक्रिया में बस मनुष्य द्वारा मनुष्य की हत्या रोकनी होती है। ऐसा होना आवश्यक भी है। मानव जीवन भी उतना ही मूल्यवान है, जितना अन्य प्राणियों का। लेकिन मनुष्य का जीवन भी एक जीवन प्रक्रिया का हिस्सा है।

अगर अन्य प्राणियों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वध होता है, तो इसमें भी जीवों की जान जाती है, मगर मानव समाज के लिए यह शांति की स्थिति से भिन्न नहीं है। दुनिया में प्रतिदिन भोजन और स्वाद के लिए जमीन पर रहने वाले 20 करोड़ जानवरों का वध किया जाता है। इसके साथ प्राकृतिक जलाशयों और कृत्रिम तालाबों से पकड़ कर मारी गई मछलियों और अन्य जलचरों को भी जोड़ें, तो प्रतिदिन तीन अरब जंतुओं की हत्या की जाती है।

इस प्रकार वर्ष भर में 36 अरब से अधिक निरीह जंतु विश्व शांति के लिए व्याकुल मानव रूपी जंतुओं के पेटों में समा जाते हैं और मानव जिह्वा को विविधतापूर्ण स्वादों से तृप्त कर जाते हैं। शांति-शांति चिल्लाने वाले मानव के लिए अरबों जानवरों की जीवन लीला शांत कर दी जाती है, जैसे उन निरीह जंतुओं के लिए शांति का कोई अर्थ ही नहीं। सर्वाधिक संहार समुद्री जीवों का होता है।

मछुआरों के जाल में केवल वही मछलियां नहीं आतीं, जिनके लिए वे जाल बिछाते हैं। उनमें अधिकांश वे जीव-जंतु होते हैं, जो उनके भोजन में नहीं आते। अनैच्छिक जंतुओं के जाल में फंसने के लिए एक तकनीकी शब्द है 'बाईकैच'। सितबंर, 2018 के आंकड़ों के अनुसार, प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को खिलाने के लिए बाईकैच के कारण 500 समुद्री जीवों की हत्या की जाती है। ये जीव भी शांति के अधिकारी हैं और इनकी शांति के बिना हमारी शांति अधूरी है।

कुछ वैज्ञानिक और विशेषज्ञ यदा-कदा मांस प्राप्त करने के लिए जानवरों को मारने के मानवीय तरीकों की बात करते हैं। ऐसा इसलिए कि गोश्त के बिना अपने मजहब को अधूरा मानने वाले, जानवरों को हलाल करके मारने की वे निरर्थक बात करते हैं। लेकिन जानवरों की हत्या का कोई भी तरीका मानवीय नहीं हो सकता। जमीन पर, मिट्टी और पानी में रहने वाले सभी जीव-जंतु एक ही जीवन-प्रक्रिया के हिस्से हैं।

किसी भी जीव के जीवन का संकट संपूर्ण जीवन के संकट की कड़ी होती है। मनुष्य प्रजाति के लिए उपलब्ध भोजन, जो शांति के लिए सबसे पहली आवश्यकता है, प्राकृतिक परिवेश से आता है। प्राकृतिक परिवेश (मिट्टी, पानी, हवा) स्वस्थ हैं, विभिन्न परिवेशों में रहने वाले जीव स्वस्थ हैं, तो मानव जाति की सभी मूलभूत जरूरतें पूरी होंगी, मानव समाजों में शांति प्रस्फुटित होगी और जीवन-दायिनी पृथ्वी पर जीवन खिलेगा-चहकेगा-महकेगा।

जीवन का खिलना-चहकना-महकना ही तो शांति की सबसे प्रखर अभिव्यक्ति है। विश्व शांति का बीज हमारी सोच में होता है। तालिबानी और आतंकवाद पैदा करने वाली सोच के बीजों को संपूर्ण रूप से नष्ट करके ही शांति के बीज धरती पर बोए जा सकते हैं, जिनकी फसलों के फल धरती की आने वाली पीढ़ियों को मिलते रहेंगे और शांति के वातावरण में धरती पर जीवन फूलता-फलता, चहकता-महकता रहेगा।

सपा का यूपी में कांग्रेस से गठबंधन पर विचार, पंजाब दलित कार्ड दे सकता है फायदा

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब से उत्तरप्रदेश को भी साध लिया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जातिवाद देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है।

चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को न सिर्फ पंजाब बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी बेहद अहम कदम माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने खासतौर पर उत्तर भारत के किसी राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर ऐसा दांव चला है जिसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में हावी होती दिख रही है।

समाजवादी पार्टी-आम आदमी सहित कई दलों के नेताओं ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया है। इस पूरे प्रकरण के बाद अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए।

भीम आर्मी के चंद्रशेखर से प्रियंका गांधी की मुलाकात कांग्रेस की इसी रणनीति का हिस्सा थी।ये ऐसा मौका है जब अखिलेश यादव की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन और दलित संवाद कार्यक्रमों के जरिए ब्राह्मण और दलितों की भी बात हो रही है।

समाजवादी लोहिया वाहिनी ने विभिन्न जिलों में 19 सितम्बर 2021 से ''गांव-गांव दलित संवाद'' कार्यक्रम शुरू किया है। फिलहाल आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का भी 29 सितंबर से 23 अक्टूबर तक कई रैलियों और चुनावी यात्राओं का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिस समय इस गठबंधन सपा-कांग्रेस के बीच बात और आगे बढ़ सकती है।

उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर-प्रदेश की 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए 'नई हवा है, नई सपा है' का नारा दिया है। जिसके बाद अखिलेश ने इस नारे के साथ-साथ मुलायम सिंह यादव के एमवाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण की परिभाषा भी बदल दी है। अखिलेश यादव सत्ताधारी बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिन्दुत्व की राह पर चल कर दवाब दे रहे हैं। ऐसे समय में जब पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री मिला है। इस पर क्रेडिट लेने में भी कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है। पार्टी के बड़े नेता विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए ये बिसात चली है।

फेडरल रिजर्व की नीतियों का असर

सतीश सिंह

पिछले दिनों जब फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने यह कहा कि फेडरल रिजर्व जल्दबाजी में ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, तो भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के बाजारों में तेजी देखी गई, जो इस बात का संकेत है कि फेडरल रिजर्व का फैसला दुनिया भर के देशों की मौद्रिक नीतियों को प्रभावित करता है। हालांकि, यह कहना अनुचित होगा कि फेडरल रिजर्व की नीतियों से दुनिया भर के देशों की मौद्रिक नीतियां पूरी तरह से प्रभावित होती हैं।

सच कहा जाए तो विभिन्न देशों की मौद्रिक नीतियां उस देश की आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों से ज्यादा प्रभावित होती हैं। फिलहाल फेडरल रिजर्व के प्रभाव से इतर दुनिया के देश कमजोर अर्थव्यवस्था और विकास की सुस्त रफ्तार के कारण भी नीतिगत दरों में कटौती करने से परहेज कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल से ही भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक समीक्षा में अपने नरम रुख को कायम रखे हुए है, जिस वजह से बाजार में अतिरिक्त तरलता की स्थिति बनी हुई है।

हालांकि, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास देश के आर्थिक परिदृश्य के सामान्य होने तक बाजार में कुछ अतिरिक्त तरलता के प्रवाह को बनाए रखना चाहते हैं, ताकि आपात स्थिति में कारोबारियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारत में कोरोना वायरस के डेल्टा ख्रलस वर्जन के संक्रमण का डर बना हुआ है और तीसरी लहर की आशंका को अभी खारिज नहीं किया गया है।

महामारी का वैसे तो अनेक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्यम (एमएसएमई) सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30 प्रतिशत का योगदान है और यह सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाले क्षेत्रों में शामिल है। सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना से एमएसएमई क्षेत्र को काफी राहत मिली है, पर अब भी इस क्षेत्र को राहत देने की आवश्यकता है।

बड़े उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों को भी मदद मुहैया कराने की जरूरत है। लिहाजा, दबावग्रस्त एमएसएमई एवं बड़े ऋण खातों को पुनर्गठित करने का काम बैंकों द्वारा किया जा रहा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में सरकारी बैंकों के प्रमुखों से आगामी त्योहारी महीनों में ऋण वितरण में तेजी लाने के लिए कहा है। लेकिन एमएसएमई सहित अन्य क्षेत्रों में अब भी ऋण का उठाव बहुत ही कम है।

मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में आर्थिक गतिविधियों में तभी तेजी आएगी, जब एमएसएमई, बड़े उद्योगों और अन्य उद्यमों में कामकाज सुचारु ढंग से शुरू होगा। संकटग्रस्त उद्योगों और कारोबारियों को तभी राहत मिलेगी, जब सरकार और बैंक अन्य राहतों को मुहैया कराने के साथ-साथ ऋण ब्याज दरों में कटौती करें या कम से कम उसे यथावत रखें। अगस्त महीने में थोक महंगाई 11.39 प्रतिशत रही, जो जुलाई महीने में 11.16 प्रतिशत थी।

जबकि खुदरा महंगाई दर 5.30 प्रतिशत रही, जो जुलाई महीने में 5.59 प्रतिशत थी। खुदरा महंगाई विगत चार महीनों में सबसे कम है, लेकिन इसमें मामूली कमी आई है। अगर महंगाई आगामी महीनों में नियंत्रण में नहीं आती है, तो केंद्रीय बैंक रेपो दर को कम करने की जगह उसे बढ़ाने पर विचार कर सकता है, जिससे कंपनियों और कारोबारियों के साथ-साथ आम आदमी को भी ऋण खातों पर बढ़ी हुई ब्याज राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

वर्ष 2021 की जून तिमाही में जीडीपी 20.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जिसका कारण आधार प्रभाव है। फिर भी, तिमाही आधार पर जीडीपी में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। लेकिन इस वृद्धि दर को कायम रखने के लिए आगामी मौद्रिक समीक्षाओं में नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करने से केंद्रीय बैंक को गुरेज करना होगा। हालांकि, बढ़ती महंगाई को देखते हुए ऐसा करना केंद्रीय बैंक के लिए आसान नहीं होगा।

मैथ्स में हैं एक्सपर्ट तो इन फील्ड में बना सकते हैं करियर

आज हम आपको बताने जा रहे हैं गणित में 8 ऐसे करियर ऑप्शन जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

छात्रों के बीच गणित विषय को कठिन विषय समझा जाता है, इसका नाम सुनते ही बहुत से छात्र दूर भागते हैं। परंतु यदि प्रारंभ से ही गणित विषय को सही प्रकार से हैंडिल किया जाए तो आपकी गणित पर अच्छी पकड़ हो सकती है। गणित विषय का अर्थ केवल जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग देना नहीं है। इस विषय में उच्च शिक्षा लेकर करियर की अपार संभावनाएं हैं। गणित विषय मनुष्य की ज्ञान की एक उपयोगी तथा आकर्षक शाखा है। इसमें अध्ययन के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत में प्राचीन काल से ही गणित की एक सुदृढ़ परंपरा रही है। प्राचीन काल के कई गणितज्ञों आर्यभट्ट, वराह मिहिर, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य इत्यादि ने तथा आधुनिक काल में डॉ गणेश प्रसाद, प्रोफेसर बीएन प्रसाद, श्रीनिवास रामानुजन इत्यादि ने गणित की सुदृढ़ नींव रखी है।

इकोनॉमिस्ट

एक इकोनॉमिस्ट आर्थिक रुझानों का अन्वेषण करके मूल्यांकन करता है। भविष्य को लेकर पूर्वानुमान जारी करता है। वह विभिन्न विषयों जैसे महंगाई, कर, ब्याज दर, रोजगार का स्तर आदि का डेटा संग्रह करता है। उस पर अनुसंधान करता है और विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्री बनने के लिए गणित विषय को जरूरी माना जाता है। एक अर्थशास्त्री बनने के लिए अर्थशास्त्र में बैचलर डिग्री होना और गणित पर अच्छी पकड़ होना आवश्यक है। इसके बाद अर्थशास्त्र, इकोमेट्रिक्स, ऐप्लाइड इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेर इंजीनियरिंग के छात्रों के करियर की नीव शुरू ही गणित के ज्ञान से होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का काम सॉफ्टवेयर डिजाइन करना और उसे डेवलप करना होता है। इस काम में छात्रों को कम्यूटर साइंस के साथ-साथ मैथ्स की थ्योरी और उनके सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। इस क्षेत्र में एक्सपर्ट छात्रों के लिए बहुत अच्छे विकल्प मौजूद है तथा अगले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं आने वाली हैं जो छात्रों के हित में मददगार साबित होंगे।

स्टैटिस्टिक्स

गणित पर जिनको महारत हासिल है उनके लिए स्टैटिस्टिक्स में कैरियर बनाना बहुत अच्छा विकल्प है। सांख्यिकीविद को डाटा का विश्लेषण करना, परिणामों को पाइ चार्ट्स, बार ग्राफ, टेबल के रूप में प्रस्तुत करने का काम करना होता है। हेल्थ केयर, शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सांख्यिकीविद की काफी मांग होती है। सांख्यिकीविद बनने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में स्नातक की डिग्री या फिर स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए।

चार्टर्ड एकाउंटेंट

चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने का पहला रूल ही गणित में दक्ष होना है। क्योंकि चार्टर्ड एकाउंटेंट यानि कि सीए का पूरा काम एकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन से जुड़ा होता है। अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि के चलते फाइनेंस और एकाउंट से जुड़े क्षेत्रों में करियर के काफी स्कोप जुड़ते जा रहे हैं जो गणित में रूचि रखने वाले छात्रों के लिए एक अच्छा करियर विकल्प का मार्ग है।

ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट

इससे जुड़े काम को एप्लाइड मैथ्स और फॉर्मल साइंस की एक शाखा के रूप में ही समझा जाता है। इसमें आधुनिक लॉजिकल विधियों जैसे की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट इन्हीं आधुनिक विधियों कि मदद से मैनेजर को सही निर्णय लेने और समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव प्रदान करते है।

बैंकिंग

अगर आपकी गणित में अच्छी पकड़ है तो आप बैंकिंग क्षेत्र में आप एकाउंटेंट, कस्टमर सर्विस, फ्रंट डेस्क, कैश हैंडलिंग, एकाउंट ओपनिंग, करंट एकाउंट, सेविंग एकाउंट, लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिकवरी ऑफिसर के प्रोफाइल्स के लिए भी कोशिश कर अपना भविष्य बना सकते है क्यूंकि इन सभी में मैथमेटिकल स्किल्स का होना जरूरी है।

मैथमेटिशियन

अगर आप मैथ को दिल से प्यार करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा माहिर हैं, तो मैथमेटिशियन बनना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। यह ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो मैथ्स के बुनियादी क्षेत्र का अध्ययन या रिसर्च संबंधी कार्य करते हैं। इसके अलावा ये लॉजिक, ट्रांसफार्मेशन, नंबर आदि समस्याओं का निर्धारण करते हैं। इस क्षेत्र में भी मैथ्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है तथा इस क्षेत्र में छात्र अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं।

कम्प्यूटर सिस्टम एनालिस्ट

कम्प्यूटर सिस्टम एनालिस्ट आईटी टूल्स का उपयोग करते हुए किसी भी एंटरप्राइजेज को लक्ष्य पूरा करने में मदद पहुंचाते हैं। यदि आपको गणित का ज्ञान नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते और इसी के विपरीत यदि आपका गणित के प्रति रुझान है तो आप आसानी से अपने काम को पूरा कर सकते हैं। ज्यादातर सिस्टम एनालिस्ट अपना काम कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं तथा इसे ठीक तरह से समझने के लिए गणित पहली नींव है।

बदलाव के लिए करें खुद को तैयार

नौकरी के दौरान अक्सर एक जैसा काम करते हुए हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जिसमें जरा-सा बदलाव भी हमें असहज कर देता है। नौकरी के दौरान अक्सर एक जैसा काम करते हुए हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जिसमें जरा-सा बदलाव भी हमें असहज कर देता है। लगातार सुविधापूर्ण स्थिति में आत्ममुग्ध रहना एक तरह से 'असुविधा'' को ही दावत देना है। अगर आप भी कंफर्ट जोन में खुद को 'कंफर्टेबल' मानकर चल रहे हैं, तो वक्त रहते संभल जाएं और ऐसा करके ही आप खुद को हर परिस्थिति में कॉन्फिडेंट रख सकेंगे।

सदाशिव पढ़ाई में अच्छे हैं। दिखने में समझदार। नौकरी जल्द शुरू कर दी थी। कुछ ही साल में अपनी पहचान भी बना ली और एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए अलग से काम करके उनका विश्वास भी हासिल कर लिया। इसका उन्हें फायदा भी मिलता रहा। पद और प्रतिष्ठा तो मिली ही, कई बार विदेश जाने का अवसर भी मिला। मगर कई साल ऐसे ही बीतने के कारण सदाशिव आत्ममुग्धता के शिकार होते चले गए। प्रभावशाली अधिकारी का संरक्षण मिला होने के कारण वे खुद को बेहद सुरक्षित महसूस करने लगे। इस बीच उन्हें कई प्रोजेक्ट मिले, पर भरपूर अवसर मिलने के बावजूद किसी में खास प्रभाव छोड़ न पाने के कारण अंतत: वे अपने मूल विभाग में ही बने रहे। यहीं उनसे चूक होती चली गई। अपने मूल विभाग के बॉस से उनकी ट्यूनिंग बनने और प्रगाढ़ होने के बजाय बिगड़ती चली गई लेकिन आत्ममुग्धता और उच्चाधिकारी की शह के कारण उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। विभागीय बॉस के उपेक्षापूर्ण नजरिये से ठेस लगने के बावजूद उनका स्वाभिमान नहीं जागा और वे निश्चिंतता के साथ टाइम पास करते रहे। इतना ही नहीं, सोशल साइट्स पर भी वे खूब दिखते और अपनी बेतुकी टिप्पणियों पर खुद ही खुश हो लेते। कुछ समय बाद स्थितियां करवट लेने लगीं। प्रभावशाली अधिकारी का प्रभाव जाता रहा और एक समय ऐसा भी आया, जब उनकी जगह कंपनी में कोई और आ गया। अब सदाशिव को सचेत हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। उनका रवैया जस का तस बना रहा। वे चाहते, तो अपने विश्वासी अधिकारी के रहते किसी और विभाग या केंद्र या प्रोजेक्ट में अच्छे पद पर शिफ्ट हो सकते थे लेकिन सुविधाजीवी और एकरस जीवन के आदी हो चुके सदाशिव ने ऐसी कोई पहल नहीं की। एक दिन जब उन्हें कुछ गलतियां बताते हुए संस्थान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तब उन्हें एहसास हुआ लेकिन तब उनके पास संभलने और सुधरने का मौका नहीं था।

भंवर है कंफर्ट जोन

सदाशिव की सच्ची कहानी महज एक उदाहरण है। आपको अपने संस्थान या दूसरी संस्थाओं, विभागों में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, जो कंफर्ट जोन में समय बिताते हुए खुश दिखेंगे। कई लोग यह भी कहते मिल जाएंगे कि अरे भाई, नौकरी तो सुरक्षित है ही, फिर काम की टेंशन में क्यों परेशान रहें! दरअसल, ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि इस प्रकार का रवैया रखकर वे खुद के नुकसान की ही नींव रख रहे हैं। स्थितियां हमेशा एक-सी नहीं रहतीं। जो लोग काम से जी चुराते हैं, नया सीखने-जानने में दिलचस्पी नहीं रखते, कभी पहल करके कोई काम नहीं करते, कोई काम कहने पर समाधान के बजाय तमाम तरह की समस्याएं ही गिनाने बैठ जाते हैं, टीम मेंबर्स से भी जिन्हें ढेरों शिकायतें होती हैं, सही मायने में उनका करियर हमेशा दांव पर लगा होता है। ऐसे लोगों को जब कभी कोई काम सौंपा जाता है, तो वे उसमें इतना विलंब कर देते हैं या फिर उसे इतना उलझा देते हैं कि बॉस को आगे उन्हें काम न देने के बारे में सोचना पड़ जाता है। ऐसे लोग अपनी इस कथित रणनीति पर भले ही खुश होते हों पर जरा सोचें, क्या वह बॉस कभी उनकी प्रशंसा-अनुशंसा करेगा और जब कभी डिमोश न कर दिया गया या इंक्रिमेंट रोक लिया गया या फिर छंटनी की स्थिति में उनका नाम ही आगे बढ़ा दिया गया, तो फिर क्या उन्हें संस्थान और बॉस की आलोचना का अधिकार होना चाहिए

उपयोगिता करें साबित

आप निजी कंपनी में काम कर रहे हों या फिर सरकारी सेवा में हों, छोटे पद पर हों या बड़े पद पर, अगर आप अपने पद की जरूरतों के अनुसार खुद की उपयोगिता साबित करने का प्रयास नहीं करते, तो एक-न-एक दिन आपको जरूर नुकसान हो सकता है। अगर आप समय रहते नहीं चेतते, तो फिर आप किसी को दोष भी नहीं दे सकते। आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है, उसे उत्साह के साथ पूरा करने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि उसमें बॉस से और समझने की या किसी सहयोगी की मदद लेने की जरूरत है, तो विनम्रता के साथ सहयोग लें। आपके प्रयास की गंभीरता स्पष्ट नजर आनी चाहिए। अगर आप छोटे-से-छोटे काम को भी सतर्कता के साथ बहुत अच्छी तरह पूरा करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपकी छवि बेहतर होगी।

हर दिन हो नया

अगर आप एकरस जीवन से बचना और खुश रहना चाहते हैं, तो अपने काम को एंजॉय करना होगा। निष्ठा ईमानदारी से काम करेंगे, तो ज्यादा कुछ मिले-न मिले, भरपूर सुकून जरूर मिलेगा। यह आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। इसके अलावा गलतियों से सबक लेने, कमियों को दूर करने और हमेशा कुछ नया सीखने की ललक रखेंगे, तो आपके आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा रहेगा और आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी उत्साह और हौसले से कर सकेंगे। इस राह पर चलकर तरक्की की सीढ़ियां भी चढ़ते जाएंगे।

इस तरह कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में जॉब

हाल ही में ग्रेजुएशन करने वालों के लिए अमेरिका में काम करने के लिए दो ऑप्शन हैं : ऑप्शनल प्रेक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) तथा एच1बी वीसा। ओपीटी ऐसे ताजा ग्रेजुएट्स के लिए एक कार्यक्रम है, जो अपनी पढ़ाई की फील्ड में कार्य अनुभव पाना चाहते हैं। इसके लिए दो शर्तें पूरी करना जरूरी है : पहली यह कि आपकी ओपीटी जॉब का सीधा संबंध आपकी डिग्री से होना चाहिए। मसलन, यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में डिग्री ली है, तो आप शेफ के रूप में नौकरी नहीं कर सकते। दूसरी शर्त यह है कि आपने जहां से डिग्री प्राप्त की है, वहां का कोई अधिकारी ओपीटी प्रोग्राम के लिए आपका नाम प्रस्तावित करे। इसलिए यह जरूरी है कि आप जहां से पढ़ाई कर रहे हैं, उस संस्थान के संपर्क में रहें और उससे अच्छे संबंध रखें। आम तौर पर ओपीटी 1 साल के लिए ही होता है। मगर यदि आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या गणित में डिग्री ली है, तो आप ओपीटी को अतिरिक्त 17 महीनों के लिए बढ़वा सकते हैं। एच1बी वीसा ऐसे लोगों के लिए है, जो किसी स्पेशिएलिटी ऑक्युपेशन में काम करते हैं। यह एक पिटिशन-बेस्ड वीसा है, यानी आपकी ओर से आपकी कंपनी इसके लिए यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के समक्ष आवेदन करेगी। एच1बी वीसा प्राप्त करने के लिए आपको किसी यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट में इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। एच1बी वीसा पर आप अमेरिका में 3 साल तक काम कर सकते हैं। इसकी अवधि बढ़वाने के विकल्प भी हैं मगर कुल मिलाकर आप एच1बी वीसा पर अमेरिका में अधिकतम 6 वर्ष तक ही काम कर सकते हैं।

उत्साह और जुनून के साथ भरें देशभक्ति की उड़ान

भारतीय वायु सेना में करियर बनाने के लिए ऊर्जावान, उत्साही युवाओं की हमेशा मांग रहती है। क्या आप इस प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। एयर फोर्स, यानी वायु सेना में करियर को प्रतिष्ठित माना जाता है और युवाओं में यह खासा लोकप्रिय भी है। इस फील्ड में यदि आप करियर बनाते हैं, तो आपका नाता देश सेवा, नवीनतम टेक्नोलॉजी और उत्कृष्ट शारीरिक मानसिक कौशल से होगा।

भारतीय वायु सेना को ऐसे युवाओं की जरूरत है, जो ऊर्जावान हों, पैशनेट हों, उत्साही हों और जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। मगर ध्यान रहे, एयर फोर्स का हिस्सा होने में खासे परिश्रम की जरूरत होती है। इसकी चयन प्रक्रिया बहुत कड़ी है। इसमें प्रेक्टिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, फिजिकल तथा मेडिकल टेस्ट, सायकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप टास्क आदि शामिल होते हैं।

कैसे हों शामिल

भारतीय वायु सेना में शामिल होने के लिए आपको राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा। यदि आपकी उम्र साढ़े 16 साल से 19 साल है, आप भारतीय नागरिक हैं और आपने फिजिक्स तथा मैथ्स विषयों के साथ 12वीं पास की है, तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। चयन के बाद उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 3 साल की गहन ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी समाप्ति पर एयर फोर्स अकादमी में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है।

ग्रेजुएट भी एयर फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। आरंभिक चयन के बाद शॉर्ट-लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एयर फोर्स ट्रेनिंग संस्थान में भेजा जाता है।

कौन-कौन सी ब्रांच

एयर फोर्स में करियर के अवसरों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है : फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच तथा ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच।

फ्लाइंग ब्रांच

इस ब्रांच में विभिन्न श्रेणियों के पायलटों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इस ब्रांच में आकर आपको उड़ान भरने के भरपूर मौके मिलेंगे। इसमें हैलिकॉप्टर पायलट, फाइटर पायलट तथा ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में ग्रेजुएट्स तथा पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अनेक अवसर हैं। पायलट ट्रेनिंग हैदराबाद से 43 किलोमीटर दूर डंडीगल स्थित एयर फोर्स एकेडमी में दी जाती है। इस ब्रांच में शामिल होने के बाद आपको आपके डेजिग्जनेशन, ट्रेनिंग व अनुभव के आधार पर विभिन्न मिशनों का हिस्सा बनाया जाएगा।

टेक्निकल ब्रांच

एयर फोर्स की टेक्निकल ब्रांच अत्याधुनिक विमानों तथा शस्त्रों के सही संचालन को सुनिश्चित करती है। यह विमानों के मेंटेनेंस तथा सर्विसिंग और एयर फोर्स स्टेशन पर कम्युनिकेशन तथा सिग्नल से संबंधित कार्यों को करने के लिए क्रमश: मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों से एयरोनॉटिकल इंजीनियर्स को नियुक्त करती है।

ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच

यह ब्रांच मानव तथा अन्य संसाधनों का प्रबंधन कर वायु सेना का संचालन करती है। दरअसल यह एक ब्रांच न होकर इसमें अनेक ब्रांच समाहित हैं, जैसे : एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, जिसके अधिकारी समस्त संसाधनों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं। इसके कुछ अधिकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर व फ्लाइट कंट्रोलर के रूप में भी काम करते हैं। इसी प्रकार अकाउंट्स ब्रांच में अकाउंट्स संबंधी तमाम काम किए जाते हैं। लॉजिस्टिक्स ब्रांच के अधिकारियों को कपड़ों से लेकर विमानों के पुर्जों तक तमाम तरह के सामान का प्रबंधन करना होता है। एजुकेशन ब्रांच के अधिकारी भविष्य के वायु सैनिकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित करते हैं। मीटियॉरोलॉजी ब्रांच के अधिकारी उड़ान भर रहे पायलटों को गाइड कर उनकी उड़ान सुरक्षित करने में मदद करते हैं।

अडानी ग्रुप कंपनी के शेयरों में लगा 10 फीसदी का अपर सर्किट

नईदिल्ली। एक अफवाह ने एनडीटीवी के शेयरों में ऐसा उछाल लाया कि 10 फीसद का अपर सर्किट लग गया। दरअसल मार्केट में यह अफवाह तेजी से फैल रही है कि अडानी ग्रुप एनडीटीवी का अधिग्रहण कर सकता है। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप दिल्ली स्थित एक मीडिया हाउस का अधिग्रहण करना चाह रहे हैं, जिसे कई लोग हृष्टअङ्क होने का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि इन अटकलों का फायदा एनडीटीवी के शेयरों में साफ दिखा। बता दें एनडीटीवी का वित्तीय प्रदर्शन खराब रहा है। कंपनी के प्रमोटर भी कर जांच के दायरे में हैं। हालांकि, पिछले एक साल में शेयर में 130 फीसदी की तेजी आई है। बीएसई पर आज एनडीटीवी का शेयर 7.20 रुपये उछल कर 79.65 रुपये पहुंच गया। वहीं, एनएसई पर यह 7.25 रुपये की छलांग के साथ 79.85 रुपये पर पहुंच गया। दोनों एक्सचेंजों में आज 10 फीसद का अपर सर्किट लग चुका है। बता दें अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा समूह की मीडिया पहल का नेतृत्व करने के लिए अनुभवी पत्रकार संजय पुगलिया को सीईओ और प्रधान संपादक के रूप में शामिल किए जाने के बाद से बाजार में अडानी का मीडिया क्षेत्र में प्रवेश हो गया है। पुगलिया इससे पहले क्विंट डिजिटल मीडिया के अध्यक्ष और संपादकीय निदेशक थे। इससे पहले उन्होंने सीएनबीसी-आवाज का नेतृत्व किया। पुगलिया ने हिंदी में स्टार न्यूज़ की स्थापना की। पुगलिया ज़ी न्यूज़ के हेड रहे और आजतक की संस्थापक टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। एक प्रिंट मीडिया के पत्रकार के रूप में उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड और नवभारत टाइ स के साथ काम किया है। 1990 के दशक के दौरान बीबीसी हिंदी रेडियो में भी उनका नियमित योगदान था।

सोना 10,000 रुपये से भी अधिक हुआ सस्ता, 60000 रुपये से नीचे आया चांदी का भाव

नईदिल्ली। सर्राफा बाजारों में सोमवार को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट के चलते 24 कैरेट सोना अब अपने ऑल टाइम हाई रेट 10000 रुपये से ज्यादा सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी 16133 रुपये सस्ती हो चुकी है। शुक्रवार के मुकाबले सोमवार को सोना जहां 125 रुपये टूटकर 46185 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है तो चांदी 1256 रुपये कमजोर होकर 60000 रुपये किलो से नीचे आ गई है। बता दें पिछले साल 7 अगस्त को सोना 56126 रुपये और चांदी 76004 रुपये पर पहुंच गई थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है। बता दें कि आईबीजेए द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य है। हालांकि, इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में जीएसटी शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते-बेचते समय आप आईबीजेए के रेट का हवाला दे सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आईबीजेए देशभर के 14 सेंटरों से सोने-चांदी का करंट रेट लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। सोने-चांदी का करेंट रेट या यूं कहें हाजिर भाव अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं पर इनकी कीमतों में थोड़ा अंतर होता है।

15वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर

नईदिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते सप्ताह तेल कीमतों में उबाल आने बीच सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 15 वें दिन कोई बदलाव नहीं किया गया। गत पांच सितंबर को इन दोनों की कीमतों में 15-15 पैसे प्रति लीटर की कमी की गयी थी। दिल्ली में आज इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल जहां 101.19 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 88.62 रुपये प्रति लीटर पर रहा। तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल 101.19 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 88.62 रुपये प्रति लीटर पर रहा। अमेरिका में कच्चे तेल की खपत बढ़ने के मद्देनजर एक सप्ताह में तेल की कीमतों में तीन फीसदी से अधिक की तेजी रही है। सोमवार को सिंगापुर में ब्रेंट क्रूड गिरकर 74.85 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 71.45 डॉलर प्रति बैरल पर खुला।

भारत की 5,000 अरब की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है एफडीआई

नई दिल्ली। डेलॉयट के सीईओ पुनीत रंजन ने कहा है कि भारत के 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) महत्वपूर्ण है। उन्होंने साथ ही कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और सिंगापुर में 1,200 उद्योगपतियों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में उनमें से 40 प्रतिशत से अधिक ने भारत में अतिरिक्त या पहली बार निवेश करने की योजना बनाने की बात कही। रंजन ने सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब भी सबसे आकर्षक एफडीआई गंतव्यों में से एक है। उन्होंने कहा, कोविड-19 के विध्वंस के बावजूद, पिछले साल आमद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। डेलॉयट के सर्वेक्षण में शामिल उद्योगपतियों ने कहा कि वे भारत में अतिरिक्त और पहली बार निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। शीर्ष बहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क के सीईओ ने कहा, मेरा मानना है कि एफडीआई, 5,000 डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षा पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से संभव है। मैं निश्चित रूप से भारत का एक बहुत बड़ा समर्थक हूं और जानता हूं कि क्या हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से निकला एक और निष्कर्ष कुशल कार्यबल का मूल्य और विशेष रूप से घरेलू आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं थीं। ये चीजें एफडीआई के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण हैं। रंजन ने कहा कि साथ ही, यह अब भी माना जाता है कि भारत व्यापार करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह है। यह धारणा सरकारी कार्यक्रमों, प्रोत्साहनों और सुधारों के बारे में कम जागरूकता के कारण बनी हुई है। उन्होंने कहा, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और सिंगापुर में सर्वेक्षण में शामिल 1,200 उद्योगपतियों में से 44 प्रतिशत ने कहा कि वे भारत में अतिरिक्त या पहली बार निवेश की योजना बना रहे हैं। पहली बार निवेश की योजना बना रहे कारोबारियों में से लगभग दो-तिहाई अगले दो वर्षों के के भीतर ऐसा करने की योजना बना रहे हैं।

खाद्य तेलों में मिलाजुला रुख, उड़द और अरहर दाल सस्ती

नईदिल्ली। विदेशी बाजारों की भारी गिरावट के बीच स्थानीय स्तर पर मांग सुस्त पड़ने से आज दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेलों में मिलाजुला रुख रहा जबकि उड़द दाल और अरहर दाल सस्ती हो गई। वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का अक्टूबर वायदा 61 रिंगिट टूटकर 4457 रिंगिट प्रति टन रह गया। वहीं, दिसंबर का अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.65 सेंट गिरकर 55.64 सेंट प्रति पौंड रह गया। वैश्विक बाजार में आई गिरावट का असर स्थानीय स्तर पर भी रहा। इस दौरान मूंगफली तेल 219 रुपये और सोया रिफाइंड 73 प्रतिशत क्विंटल चढ़ गये। वहीं, सरसों तेल, सूरजमुखी तेल, पाम ऑयल और वनस्पति तेल के भाव पिछले स्तर पर टिके रहे। आवक और उठाव बराबर रहने से मीठे के बाजार में चीनी और गुड़ की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ और उनके भाव पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर पड़े रहे।

लिवाली के दबाव में रुपया 26 पैसे लुढ़का

मुंबई । दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने के साथ ही आयातकों और बैंकरों की लिवाली के दबाव में सोमवार को अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 26 पैसे लुढ़ककर 73.74 रुपये प्रति डॉलर रह गया। पिछले कारोबारी दिवस रुपया चार पैसे की बढ़त लेकर 73.48 रुपये प्रति डॉलर रहा था। कारोबार की शुरुआत में रुपया 34 पैसे की बड़ी गिरावट लेकर 73.82 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और सत्र का यही न्यूनतम स्तर भी रहा। हालांकि बिकवाली के बल पर यह 73.62 रुपये प्रति डॉलर के उच्चतम स्तर पर भी पहुंचा। अंत में पिछले दिवस के 73.48 रुपये प्रति डॉलर के मुकाबले 26 पैसे लुढ़ककर 73.74 रुपये प्रति डॉलर रह गया।

राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू इस्पात की खपत बढ़ाने की जरूरत: सिंह

नईदिल्ली । केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने यहां भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) से जुड़े एकीकृत (इंटीग्रेटेड) इस्पात उत्पादकों (आईएसपी) के प्रतिनिधियों से बात की। आईएसए का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सदस्य मिलकर देश में लगभग 90 प्रतिशत स्टील का उत्पादन करते हैं।

मुनाफा वसूली का शिकार हुआ बाजार

सेंसेक्स 525 अंक लुढ़ककर 59 हजार अंक के नीचे, निफ्टी भी 188 अंक गिरा

मुंबई । दुनिया के कई प्रमुख केंद्रीय बैंकों की इसी सप्ताह होने वाली बैठक से पहले निवेशकों की सतर्कता से विदेशी बाजारों में आई गिरावट के बीच ऊंचे भाव पर हुई चौतरफा मुनाफावसूली के दबाव में सोमवार को घरेलू शेयर बाजार करीब एक प्रतिशत तक लुढ़क गया। दोपहर तक 59 हजार अंक के आसपास कारोबार कर रहा बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स दो बजे के बाद शुरू हुयी बिकवाली के दबाव में 524.96 अंक की बड़ी गिरावट लेकर 59 हजार अंक के नीचे 58,490.93 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 188.25 अंक टूटकर 17396.90 अंक पर रहा। निवेशकों ने दिग्गज कंपनियों की तरह छोटी और मझौली कंपनियों में भी जमकर मुनाफा काटा।

बीएसई का मिडकैप 447.97 अंक गिरकर 24,598.51 अंक और स्मॉलकैप 516.52 लुढ़ककर 27,490.27 पर आ गया। सत्र के दौरान बीएसई में कुल 3507 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2331 गिरावट पर जबकि 1041 बढ़त पर रहे वहीं 135 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह निफ्टी की 43 कंपनियों के शेयरों ने गोता लगाया जबकि सात में तेजी रही। सेंसेक्स की शुरुआत कमजोर रही और यह 381.2 अंक की गिरावट के साथ 58,634.69 अंक पर खुला और लिवाली के बल पर दोपहर तक 59,202.56 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

इनके शेयर गिरे

विश्व के अधिकांश बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स में एफएमसीजी की 0.68 प्रतिशत की बढ़त को छोड़कर शेष 18 समूह के शेयर गिरे। इस दौरान धातु समूह ने सबसे अधिक 6.80 प्रतिशत का नुकसान उठाया। इसी तरह बेसिक मैटेरियल्स 4.14, रियल्टी 2.16, यूटिलिटीज 1.92 , पावर 1.88, तेल एवं गैस 1.78, वित्त 1.75, इंडस्ट्रियल्स 1.72, हेल्थकेयर 1.70, बैंकिंग 1.66, ऑटो 1.47, कैपिटल गुड्स 1.10 और सीडीजीएस के शेयर 1.08 प्रतिशत उतर गए। इनके अलावा अन्य समूह शेयर भी 0.93 प्रतिशत टूटे। कारोबार के दौरान 22 कंपनियों के शेयर गिरे जबकि आठ में बढ़त रही। इस दौरान टाटा स्टील ने सबसे अधिक 9.53 प्रतिशत का नुकसान उठाया। इसी तरह एसबीआई 3.69, इंडसइंड बैंक 3.50, एचडीएफसी 2.90, डॉ. रेड्डी 2.30, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.25, अल्ट्रा सिमको 2.07, सन फार्मा 1.78, एक्सिस बैंक 1.55, एचडीएफसी बैंक 1.51, टेक महिंद्रा 1.49, आईसीआईसीआई बैंक 1.38, बजाज ऑटो 1.31, मारुति 1.13, पावर ग्रिड 1.09 और एशियन पेंट के शेयर 1.04 प्रतिशत की गिरावट पर रहे। इनके अलावा शेष अन्य कंपनियों ने भी 0.82 प्रतिशत तक का गोता लगाया। शुरुआती कारोबार में निफ्टी भी 141.3 अंक कमजोर होकर 17,443.85 अंक पर खुला और लिवाली के दम पर 17,622.75 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बिकवाली होने से यह 17,361.80 अंक के निचले स्तर तक लुढ़क गया। अंत में पिछले दिवस के 17,585.15 अंक की तुलना में 1.07 प्रतिशत गिरकर 17,396.90 अंक पर रहा।

इनके शेयर चढ़े

ब्रिटेन का एफटीएसई 1.63 प्रतिशत, जर्मनी का डैक्स 2.37 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसैंग 3.30 प्रतिशत लुढ़क गया जबकि जापान का निक्केई 0.58 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.19 प्रतिशत की बढ़त पर रहे। मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में हिंदुस्तान यूनीलीवर 2.84 प्रतिशत, बजाज फिनसर्व 1.10 प्रतिशत, आईटीसी 1.08 प्रतिशत, एचसीएल टेक 0.88 प्रतिशत, नेस्ले इंडिया 0.70 प्रतिशत, ओएनजीसी 0.67 प्रतिशत, बजजा फाइनेंस 0.21 प्रतिशत और रिलायंस 0.15 प्रतिशत शामिल रहीं।

एसबीआई ने कस्टमर केयर नंबर को लेकर ग्राहकों को किया सावधान

नईदिल्ली । कोरोना महामारी की वजह से जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिला है, वह बैंकिंग सेक्टर। बैंक और उससे जुड़े ढेर सारे काम अब घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। बैंक भी इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि ग्राहकों को कम से कम ब्रांच आना पड़े। लेकिन इस सुविधा ने एक समस्या भी खड़ी कर दी है। पहले की अपेक्षा अब डिजिटल फ्रॉड काफी बढ़ गया है। यानी आपकी एक चूक और पूरा अकाउंट खाली। इसी की देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को फेक कस्टमर केयर नंबर को लेकर सतर्क किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बैंक ने ग्राहकों फेक कस्टमर नंबर को लेकर सावधान किया है। वीडियो में एक व्यक्ति फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर फोन पर गलती से फोन कर देता है। जिसमें वह कार लोन के विषय में जानकारी मांगता है। दूसरी तरफ से अकाउंट डिटेल्स पूछे जाते हैं। जब कस्टमर अकाउंट डिटेल्स बता देता है तब जवाब आता है कि आपका अकाउंट बंद है। अपना डेबिट कार्ड नंबर साझा करिए और इसी तरह धोखे में सारी जानकारी लेकर अकाउंट में सेंध लगाई जाती है। बैंक की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ऐसी जानकारी किसी से साझा ना करें साथ ही बैंक ने अपने कस्टमर केयर का नंबर भी जारी किया है। सबसे बेस्ट है कि अगर आपको कस्टमर केयर का नंबर चाहिए तो जरूरी है कि आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां दिए गए नंबर का ही यूज करें। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो आप तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल करें। और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। बैंक ने ट्विटर पर अपनी जानकारी देते हुए कस्टमर केयर का नंबर साझा किया है।

नॉमिनी और उत्तराधिकारी में जानें अंतर

खातेदार की मृत्यु के बाद जानें बैंक खाते के पैसे या बीमा रकम का मालिक कौन

नई दिल्ली । अक्सर लोग नॉमिनी और उत्तराधिकारी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सही मायनों में दोनों के मतलब ही नहीं अधिकार भी अलग-अलग हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, नॉमिनी किसी भी चल-अचल संपत्ति का मालिक नहीं होता है। वह केवल आपके पैसों का रखवाला होता है। वहीं, कानूनी उत्तराधिकारी वह होता है जो व्यक्ति के निधन पर उसकी संपत्ति प्राप्त करने का आधिकारिक रूप से हकदार होता है।

नॉमिनी को मालिकाना हक नहीं : कानूनी जानकार बताते हैं कि कोई बीमा कंपनी की पॉलिसी में नॉमिनी हो या बैंक खाते में, नॉमिनी होना अपने आप में मालिकाना हक नहीं देता है। अगर खाताधारक ने किसी को नॉमिनी बनाया है या इंपॉलिसी में बीमाधारक ने किसी को नॉमिनी बनाया तो वह नॉमिनी सिर्फ लेनदेन की सहूलियत के लिए है। नॉमिनी होने का मतलब यह नहीं है कि वह शख्स उस बैंक खाते के पैसे या बीमा रकम का मालिक हो गया। अगर बैंक अकाउंट होल्डर ने कोई वसीयत नहीं की हुई है या बीमाधारक की कोई वसीयत नहीं है तो रकम तमाम कानूनी वारिसों में बराबर बंटेगी।

कौन होता है उत्तराधिकारी : संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद उसके संबंधियों को संपत्ति सौंप दी जाती है। जन्म ग्रहण करने के साथ-साथ पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्र, पुत्री, विधवा, मां क्लास-1 उत्तराधिकारी में आते हैं। वहीं पिता, पुत्र व पुत्री का बेटा व बेटी, भाई, बहन, भाई व बहन की संतान क्लास-2 में आते हैं। अगर मृतक मुस्लिम है तो शरीयत कानून 1937 के हिसाब से संपत्ति का वारिस तय होगा। क्रिस्चन के मामले में वारिस आमतौर पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत तय होता है। इसके तहत पति, पत्नी, बेटे और बेटियां वारिस माने गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर किसी ने अपनी कमाई बैंक में जमा की हुई है और अकाउंट में किसी को नॉमिनी बना रखा है। मसलन अपने बड़े बेटे को नॉमिनी बनाया लेकिन अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं की है। अगर उस शख्स की मौत हो जाए तो नॉमिनी बैंक से पैसे तो निकाल सकता है लेकिन मृतक के जितने भी क्लास-1 उत्तराधिकारी होंगे, उन सभी का पैसे पर बराबर का दावा होगा। उनका बाकी संपत्ति पर भी बराबर का हक होगा। अगर क्लास-1 उत्तराधिकारियों में से कोई नहीं हो तब क्लास-2 उत्तराधिकारियों में बंटवारा होगा।

जीईएम पोर्टल पर 28,300 से अधिक कारीगरों और 1,49,422 बुनकरों ने कराया पंजीकरण

बुनकरों और कारीगरों को बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान आरंभ किया गया अभियान

नईदिल्ली । बुनकरों और कारीगरों को बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के एक प्रयास के तहत उन्हें जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है और पोर्टल पर 30 अगस्त तक 28,374 कारीगरों और 1,49,422 बुनकरों का पंजीकरण हो चुका था।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस पोर्टल के माध्यम से वे अपने उत्पादों को सीधे सरकारी विभागों को बेच सकें। इससे हथकरघा और हस्तशिल्प में काम करने वाले कारीगरों, बुनकरों, सूक्ष्म उद्यमियों, महिलाओं, आदिवासी उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों जैसे उन विक्रेता समूहों की भागीदारी बढ़ेगी, जिन्हें सरकारी बाजारों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जो अपर्याप्त अवसरों से जूझते हैं। पोर्टल पर 30 अगस्त, 2021 तक 28,374 कारीगरों और 1,49,422 बुनकरों का पंजीकरण हो चुका था। जीईएम ने जुलाई 2020 में हथकरघा विकास आयुक्त और हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों की सहायता से बुनकरों एवं कारीगरों का विक्रेता पंजीकरण तथा उन्हें पोर्टल से जोड़ने की शुरुआत की थी। साथ ही 56 हस्तशिल्प सेवा केंद्रों और 28 बुनकर सेवा केंद्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल किया गया। हथकरघा उत्पादों के लिए 28 विशिष्ट उत्पाद श्रेणियां बनाई गई हैं। साथ ही हस्तशिल्प उत्पादों के लिए 170 कस्टम उत्पाद श्रेणियां बनाई गईं। भारतीय हथकरघा और भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिए विशेष वेब-बैनर और बाजार पृष्ठ विकसित किए गए हैं जिनकी मदद से विभिन्न सरकारी खरीदारों को ऐसे उत्पादों की आपूर्ति करने में सक्षम कारीगरों, बुनकरों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक कंपनियों द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

अगस्त में रोजगार के अवसरों में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी

नई दिल्ली । कोरोना महामारी का झटका झेल चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था के अब धीरे-धीरे पटर पर लौटने से इस वर्ष अगस्त में रोजगार के अवसरों में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

शोध सलाह देने वाली कंपनी मॉन्स्टर की सोमवार को जारी रोजगार विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2021 में नौकरी गतिविधि में जुलाई के मुकाबले एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर इस अवधि में नौकरी पोस्टिंग में साल-दर-साल 14 की बढ़ोतरी हुई है। त्योहारी सीजन को लेकर अगस्त में गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, लेदर, रत्न और आभूषण क्षेत्र में 24 प्रतिशत तथा उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र में राजेगार में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके अलावा कार्यों के मामले में, विपणन और संचार क्षेत्र के रोजगार में महीने-दर-महीने सबसे अधिक 17 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और यह बढ़ोतरी खासकर मेट्रो शहरों में रही है। लोगों को नौकरी देने के मामले में बेंगलुरु में 59 प्रतिशत, हैदराबाद में 34 प्रतिशत, पुणे में 40 प्रतिशत और चेन्नई में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 14 प्रतिशत और मुंबई में 16 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई है। कोयंबटूर जैसे टियर दो शहरों में नौकरी पोस्टिंग में सात प्रतिशत की आशाजनक वृद्धि देखी गई है।

निर्यातकों की सहायता के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन होगी शुरू: गोयल

नईदिल्ली । केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए अमृत महोत्सव सप्ताह के राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुये कहा कि सरकार निर्यातकों की सहायता और समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन को संस्थागत रूप देने जा रही है। श्री गोयल ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सेज नोएडा में वाणिज्य शपथ के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि हमारा उद्देश्य'ब्रांड इंडिया'को गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रतिभा और नवाचार का प्रतीक बनाना है। श्री गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास और निर्यात में सराहनीय प्रगति की है। यूपी में कानून और व्यवस्था में सुधार से व्यापार करना बहुत आसान और सुरक्षित हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय'आजादी का अमृत महोत्सव'समारोह के हिस्से के रूप में प्रगतिशील भारत के 75 साल का उत्सव मनाने के लिए, आज देश भर में 7 दिनों तक चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरूआत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों के लिए संयुक्त रूप से एक रोडमैप तैयार करने और विश्व व्यापार में भारत को अग्रणी देश बनाने के लिए योगदान देने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र के सुधारों ने विकास को कल्याणकारी बना दिया है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर विस्तार, शौचालयों का निर्माण आदि एक बड़ी सफलता है और इन सभी ने विकास को समावेशी बनाया है।

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में गौतम अडानी का बड़ा दांव, अंबानी को भी छोड़ दिया पीछे

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने तीन वर्ष में स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन ईंधन में 75,000 करोड़ रुपये (10 अरब डॉलर) निवेश की घोषणा की थी। अब गौतम अडानी ने भी 20 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है।

एजेंसी,नई दिल्ली। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत के दो सबसे दौलतमंद अरबपति- मुकेश अंबानी और गौतम अडानी आमने-सामने हैं।

बीते दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने तीन वर्ष में स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन ईंधन में 75,000 करोड़ रुपये (10 अरब डॉलर) निवेश की घोषणा की थी। अब गौतम अडानी ने भी 20 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। क्या कहा गौतम अडानी ने: जेपी मॉर्गन इंडिया इन्वेस्टर समिट में गौतम अडानी ने अपने प्लान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि अगले चार वर्ष में अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन क्षमता को तीन गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने, सभी डेटा सेंटर को नवीकरणीय ऊर्जा से चलाने, 2025 तक अपने बंदरगाहों के कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की भी योजना है। वहीं, 2025 तक हरित प्रौद्योगिकियों में पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा खर्च करने की योजना बनायी है। उन्होंने कहा कि 20 अरब डॉलर का निवेश रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, कलपुर्जों के निर्माण, ट्रांसमिशन और वितरण के क्षेत्रों में किया जाएगा। गौतम अडानी ने आगे कहा कि हम दुनिया में सबसे सस्ते ग्रीन इलेक्ट्रॉन के निर्माता बनने की राह पर हैं। इससे पहले हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने भी तीन वर्ष में स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन ईंधन में 75,000 करोड़ रुपये (10 अरब डॉलर) निवेश की घोषणा की है। अंबानी ने इस महीने कहा था कि एक दशक में रिन्यूएबल एनर्जी से एक डॉलर प्रति किलोग्राम की लागत पर हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। बता दें कि हाइड्रोजन में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है और इसे उद्योग और ऑटोमोबाइल में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

सार समाचार

जापान: 4 अक्टूबर को तय होगा नया पीएम

तोक्यो। जापान सरकार ने मंगलवार को नवंबर में होने वाले आम चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री का निर्धारण करने के लिए 4 अक्टूबर को असाधारण संसद सत्र बुलाने के अपने फैसले की घोषणा की। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 29 सितंबर को होने वाले सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व के चुनाव से निवर्तमान प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा के अगले प्रमुख को प्रभावी ढंग से तय करने की उम्मीद है, जो इस महीने के अंत में इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि एलडीपी शक्तिशाली निचले को नियंत्रित करता है। चार उम्मीदवारों, पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा, पूर्व संचार मंत्री सानाए ताकाची, टीकाकरण मंत्री तारो कोनो और एलडीपी के कार्यकारी कार्यवाहक महासचिव सीको नोडा ने एलडीपी दौड़ के लिए अपनी बोलियों की घोषणा की है। नए प्रधानमंत्री द्वारा उसी दिन एक नया मंत्रिमंडल शुरू करने और बाद में उप मंत्रियों और अन्य कर्मियों पर निर्णय लेने की उम्मीद है। सभी चार उम्मीदवारों ने कहा है कि वे एक नीति भाषण देंगे और निर्वाचित होने पर विपक्षी दलों के साथ सवाल-जवाब का सत्र आयोजित करेंगे। इस मामले में, आम चुनाव के लिए दो सबसे संभावित समय सारिणी 26 अक्टूबर को 7 नवंबर को मतदान के लिए प्रचार शुरू करना है या 2 नवंबर को 14 नवंबर को मतदान के लिए प्रचार करना है। चार उम्मीदवारों के उद्योग समूहों और स्थानीय संगठनों पर विचारों का आदान-प्रदान जारी रखने का अनुमान है। गुरुवार से, उन्हें चार दिनों तक चलने वाले ऑनलाइन नीति बहस सत्रों में जनता के सवालों के जवाब देने की योजना है। प्रतिनिधि सभा का अगला चुनाव 21 अक्टूबर के बाद के महीनों में होने की उम्मीद है जब मौजूदा निचले सदन के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

अफगानिस्तान के 19 अवैध अप्रवासी इस्तांबुल में हिरासत में लिए गए

इस्तांबुल। तुर्की के सुरक्षा बलों ने देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में 19 अवैध अफगान प्रवासियों को हिरासत में लिया है। डेमिरोरेन समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्तांबुल नगरपालिका पुलिस इकाइयों ने सोमवार को शहर के यूरोपीय हिस्से में सुल्तानगाजी जिले में संदेह के आधार पर एक वैन को रोका। समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि टीमों ने अप्रवासियों को वाहन के अंदर पाया और पुलिस बलों को सूचित किया। इन अप्रवासियों ने कथित तौर पर इस्तांबुल से लगभग 240 किमी दूर उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत एडिरने में जाने की कोशिश की, ताकि वे ग्रीस में जा सकें। तुर्की, यूरोप जाने के रास्ते में शरण चाहने वालों के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु, तालिबान द्वारा पिछले महीने के अधिग्रहण के बाद देश से भागने वाले अफगान शरणार्थियों की आमद देखी जा रही है। देश 40 लाख से लाख शरणार्थियों की मेजबानी करता है, जिसमें इसकी सीमाओं के भीतर, ज्यादातर इस्तांबुल में 36 लाख सीरियाई शामिल हैं।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल में किया फेरबदल

ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बटरे फर्नांडीज ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया और गवर्नमेंट हाउस में द्विशताब्दी संग्रहालय में एक समारोह के दौरान नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने मंगलवार को बताया कि फर्नांडीज ने निवर्तमान मंत्रियों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के नवीनीकरण का उद्देश्य अर्जेंटीना के मतदाताओं के एक हिस्से को जवाब देना है जो स्पष्ट रूप से कोविड -19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और ठीक नहीं हुए हैं। उत्तर पश्चिमी तुकुमान प्रांत के गवर्नर जुआन मंजूर को कैबिनेट प्रमुख नियुक्त किया गया, जिसमें सैंटियागो कैफिएरो ने विदेश मामलों और वरसिप मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए उस पद को छोड़ दिया था। इसके अलावा, राष्ट्रपति ने एनीबाल फर्नांडीज को सुरक्षा मंत्री, जूलियन डोमिंगुएज को कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन मंत्री और जैम पेर्जकि को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया। डैनियल फिल्मस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में पदभार संभाला, जबकि जुआन रॉस को संचार और प्रेस के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। कैबिनेट में फेरबदल 12 सितंबर के प्राथमिक चुनावों के मद्देनजर हुआ, जिसमें देश के 24 प्रांतों में से 17 में सत्ताधारी गठबंधन एवरीबडी फंट (फ्रेंट डी टोडोस) हार गया था।

ऑस्ट्रेलिया राजधानी में अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य समर्थन बढ़ाएगा

कैनबरा। ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र (एसीटी) के मुख्यमंत्री एंड्रयू बर्र ने मंगलवार को क्षेत्र में चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के बीच मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्थन बढ़ाने की घोषणा की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बर्र ने कहा कि एसीटी सरकार राजधानी कैनबरा के क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य, शराब और नशीली दवाओं की सेवाओं का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त 1.4 करोड़ डॉलर (1 करोड़ डॉलर) का निवेश करेगी। उन्होंने कैनबरा के कोरोनावायरस लॉकडाउन का वर्णन किया, जो 12 अगस्त से शुरू हुआ और अब 15 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है। बर्र ने संवाददाताओं से कहा, फिलहाल ठीक नहीं होना ठीक है और समर्थन उपलब्ध है। एसीटी सरकार से मिलने वाली फंडिंग के शीर्ष पर, संघीय सरकार ने कैनबरा मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक हेड टू हेल्थ को समर्थन देने के लिए 25 लाख डॉलर का वचन दिया। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने एक बयान में कहा, कई ऑस्ट्रेलियाई, विशेष रूप से हमारे युवा, इसे वास्तव में कठिन बना रहे हैं। हंट ने कहा, मौजूदा प्रकोप और लॉकडाउन अत्यधिक दबाव और संकट पैदा कर रहे हैं और यह महत्वपूर्ण है कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों की मानसिक और भावनात्मक भलाई का समर्थन करना जारी रखें। यह तब आया है जब अधिनियम ने मंगलवार को 16 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोविड -19 मामलों की सूचना दी, जो सोमवार को सात मामले थे। ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार सुबह देशभर में 1,641 नए पुष्ट मामले दर्ज किए, जिससे कुल संक्रमण की संख्या 87,101 हो गई, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,167 हो गई है।

आम चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन का जलवा कायम, संसदीय चुनाव में हासिल की जीत

वाशिंगटन (एजेंसी)।

रूस में हुए संसदीय चुनाव में इस बार भी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने बाजी मारी है। चुनावी नतीजों के परिणाम में पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने जोरदार बहुमत हासिल कर आलोचकों का मुंह बंद करा दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, सत्ताधारी पार्टी के 20 फीसदी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि, 33 फीसदी वोटों की गिनती में पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया ने 45त्न वोट हासिल किया है। पुतिन के विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी ने 22 फीसदी ही वोट हासिल किए। बात करें साल 2016 के संसदीय चुनाव की तो उसकी तुलना में पुतिन की पार्टी का प्रदर्शन इस साल के चुनाव में काफी कमजोर रहा। साल 2016 के चुनाव में पार्टी ने 54 फीसदी वोट हासिल किया था। बता दें कि पुतिन की पार्टी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि, विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी ने लगातार पुतिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और समर्थकों ने कई अभियान भी चलाए जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। वहीं विपक्षी नेता नवलनी के समर्थकों ने आरोप लगाते हुए साफ कहा कि, यह चुनाव एकमात्र दिखावा है और अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो यूनाइटेड रशिया पार्टी हार जाती।

विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन पर काम विकसित देशों की मदद पर निर्भर: भारत

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)।

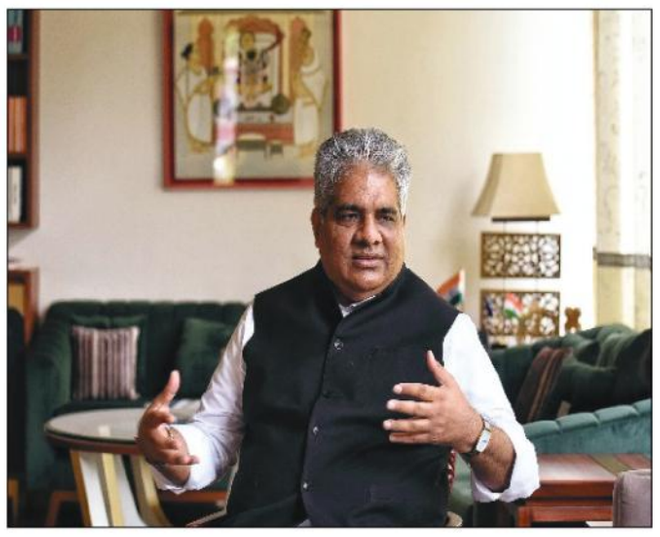

भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाई गई एक बैठक में दोहराया कि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन पर काम करने की महत्वाकांक्षी योजना पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की मदद पर निर्भर है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से 2009 में किए गए प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर के अपने वादे को पूरा करने का आह्वान किया।

न्होंने कहा कि 'कॉप 26' को कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण तथा दायरा, पैमाना एवं गति में जलवायु वित्त पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने आगामी 'सीओपी26' सहित जलवायु परिवर्तन संबंधित किसी भी बातचीत में सफल परिणाम के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रुपरेखा (यूएनएफसीसी) प्रक्रिया के सिद्धांतों को कायम रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि बैठक में, जलवायु संकट से मुकाबला करने के लिए आवश्यक वित्त, अनुकूलन आदि पर महत्वपूर्ण जलवायु कार्रवाई पर चर्चा की गयी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नवंबर में ग्लासगो में होने वाले 26वें 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' (सीओपी26) से पहले कुछ नेताओं की बैठक बुलाई थी।

पर्यावरण मंत्री यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा सहित भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की चर्चा की।

अमेरिका पूरी तरह से टीका लगाए गए विदेशी आगंतुकों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील देगा

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका अब कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाए हुए विदेशी आगंतुकों को देश में प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा। व्हाइट हाउस ने नीतिगत बदलावों की घोषणा करते हुए कहा कि वायरस के संचरण को रोकने के लिए लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी।

व्हाइट हाउस में कोविड -19 प्रतिक्रिया समन्वयक ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, जो लोग अमेरिकी नागरिक नहीं हैं और जो देश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस बात का प्रमाण देना होगा कि वे पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके हैं और प्रस्थान के तीन दिनों के भीतर एक निगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, क्योंकि वे यूएस-बाउंड फ्लाइट, जेफ जिएंट्स में सवार हैं। समाचार एजेंसीकी रिपोर्ट के मुताबिक जिएंट्स के अनुसार, अमेरिका में प्रवेश करने वाले पूरी तरह से टीकाकरण वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अब 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन्होंने यह भी कहा कि नए नियम नवंबर की शुरूआत में प्रभावी होंगे ताकि सरकारी एजेंसियों और एयरलाइनरों को तैयारी करने का समय दिया जा सके। अमेरिका लौटने वाले असंबद्ध अमेरिकियों के लिए, समन्वयक ने कहा कि वे कठोर परीक्षण आवश्यकताओं के अधीन होंगे, जिसमें प्रस्थान के एक दिन के भीतर एक परीक्षण और इस बात का प्रमाण देना होगा कि उन्होंने अमेरिका पहुंचने के बाद परीक्षण कराया है।

जिएंट्स ने कहा कि विशिष्ट टीके जो एक यात्री को पूरी तरह से टीकाकरण के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अमेरिकी मीडिया पिंटों के अनुसार परिचित लोगों का हवाला देते हुए टीकाकरण आवश्यकताओं के अपवादों में ऐसे बच्चे शामिल हैं जो अभी तक शॉट्स के लिए पात्र नहीं हैं। जीएंट्स के अनुसार, इस बीच, सीडीसी आने वाले हफ्तों में और ज्यादा कड़े संपर्क अनुरेखण आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिसमें यूएस-बाउंड अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के फोन नंबर और ईमेल पते की जानकारी शामिल है। जीएंट्स ने यह भी कहा कि कनाडा और मैक्सिको के साथ भूमि सीमा क्रॉसिंग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियम अपरिवर्तित रहे। यह विदेशों में उन लोगों को भी देगा जो अमेरिका में परिवार से अलग हो गए हैं और अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने का मौका देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन 24 सितंबर को वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 24 सितंबर को वाशिंगटन में वार्ता करेंगे और उसमें व्यापार, निवेश और रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को यह जानकारी दी। श्रृंगला ने बताया कि मोदी बुधवार को अमेरिका रवाना होंगे और रविवार को लौटेंगे। प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और विदेश सचिव श्रृंगला भी शामिल रहेंगे।

श्रृंगला ने प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी और बाइडन के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में कट्टरपंथ और आतंकवाद के अलावा अन्य बड़े क्षेत्रीय मुद्दों से निपटने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भी चर्चा होनेकी संभावना है। अमेरिकी नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के अलावा प्रधानमंत्री वाशिंगटन में 24 सितंबर को 'क्वाड' सम्मेलन में भी भागीदारी करेंगे, जिसमें समकालिन वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। वाशिंगटन में अपनी बैठकों के बाद मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शरीक होने के लिए न्यूयार्क की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री के न्यूयार्क में 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय आम बहस को संबोधित करने का कार्यक्रम है।

तालिबान ने कार्यवाहक सरकार में अन्य मंत्रियों को किया शामिल

काबुल (एजेंसी)।

अफगानिस्तान में नवगठित तालिबान की कार्यवाहक सरकार ने शेष मंत्रियों और सदस्यों को नामित किया है। कार्यवाहक सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मुजाहिद ने एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, कैबिनेट के नए सदस्य पेशेवर व्यक्तित्व हैं, जिनमें डॉक्टर और उच्च शिक्षित व्यक्ति भी शामिल हैं। मुजाहिद ने कहा कि नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा के आदेश के अनुरूप नियुक्त किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि एक अनुभवी व्यवसायी, हाजी नुरुदीन अजीजी को वाणिज्य के लिए कार्यवाहक मंत्री और कलंदर एबाद को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कार्यवाहक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मुजाहिद ने यह भी उम्मीद जताई कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस्लामिक अमीरात को मान्यता देगा।

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक स्टेट, अल कायदा या अफगानिस्तान में किसी भी अन्य आतंकवादी समूहों की उपस्थिति को खारिज करते हुए कहा कि इस्लामिक अमीरात किसी भी चरमपंथी संगठन को नष्ट करने में सक्षम है और वह किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की किसी भी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। टोलो न्यूज ने बताया कि प्रवक्ता ने यह भी घोषणा की कि नई सरकार का उद्घाटन समारोह इस समय लोगों को सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण रद्द कर दिया गया है। देश की आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि घरेलू राजस्व बुनियादी जरूरतों के लिए पर्याप्त हो सकता है। हम सभी राजनयिक माध्यमों का उपयोग अफगान संपत्तियों को मुक्त करने के लिए कर रहे हैं।

महिला मामलों के मंत्रालय और लड़कियों की शिक्षा के बारे में पूछे जाने पर मुजाहिद ने कहा कि कार्यवाहक कैबिनेट काम और शिक्षा के लिए महिलाओं की मांगों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, हम प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि लड़कियां अपनी शिक्षा फिर से शुरू कर सकें।

ईरान के टॉप वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की दिनदहाड़े हत्या, इजरायल को ठहराया गया जिम्मेदार

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

ईरान के टॉप वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की देश की राजधानी तेहरान में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई है। बता दें कि इस हत्या के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। परमाणु बम कार्यक्रम के जनक के नाम से जाने वाले मोहसिन फखरीजादेह की कार पर गोलियों की बौछार कर उनकी हत्या कर दी गई। मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के बाद से पूरे पश्चिम एशिया में कोहराम मच गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा गया कि, आतंकियों ने एक शीर्ष ईरानी वैज्ञानिक की हत्या कर दी है। ऐसी हरकत साजिश को अंजाम देता है, जिसमें इजरायल की भूमिका के गंभीर संकेत दर्शाते हैं।

बता दें कि, ईरान के इस बयान पर इजरायल ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, वैज्ञानिक की हत्या एक ऐसे समय पर हुई है जब ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले की योजना बना रहे थे। लेकिन अब जब अमेरिका में बाइडेन की सत्ता आ गई है तो अब जो बाइडेन एक बार फिर ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुपक्षिय समझौते करने को इच्छुक है। इसके अलावा, यह हत्या ऐसे समय पर हुई है जब इजरायल के पीएम, अमेरिका के विदेश मंत्री और सऊदी अरब के राजकुमार ने एक गोपनीय बैठक की थी।ईरान के टॉप वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या अब्सार्ड शहर में की गई है। हत्या के समय वहां के लोगों ने जोरदार धमाके और गोलियां चलने की आवाजें सुनी। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो पर वायरल हो रहा है जिसमें मोहसिन फखरीजादेह की कार को गोलियों से छलनी किया जा रहा है। हमलावरों ने कार को जबरदस्ती रोका और गोलियां चलाना शुरू कर दी , इसमें 3 से 4 लोगों की मौत हो गई।

फिर से एक बार कनाडा में ट्रूडो सरकार! लिबरल की वापसी के चांस लेकिन बहुमत से दूर, फिर से सिख नेता दिलाएंगे सत्ता?

नई दिल्ली (एजेंसी)।

कनाडा के मध्यावधि चुनाव के नतीजे आ गए और तमाम तरह की अटकलों पर भी विराम लग गया। जनता ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को जीत दिलाई है। ट्रूडो के दो साल पहले ही चुनाव कराने के फैसले पर उठते सवालों को चुनावी नतीजों के जरिये जवाब भी मिल गया है। एक बात जरूर है कि लिबरल पार्टी ने किसी भी पार्टी की तुलना में सबसे अधिक सीटें हासिल की हैं। लेकिन वह पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रहे हैं। लिबरल पार्टी 148 सीट पर आगे है जबकि कंजरवेटिव पार्टी 103 सीटों पर आगे है, ब्लॉक क्यूबेकोइस 28 और वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 22 सीटों पर आगे है। फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ट्रूडो पर्याप्त सीटें जीत पाएंगे और अन्य पार्टियों के सहयोग के बिना किसी कानून को पारित करा पाएंगे। लेकिन वह इतनी सीटें जरूर जीत जाएंगे उन्हें पद से हटाने का खतरा नहीं रहेगा।

170 के आंकड़े से अभी दूर

कनाडा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 38 फीसदी वोट्स की जरूरत होती है। ताकि संसद में बहुमत हासिल किया जा सके। कनाडा की संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं और एक पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए 170 सीटों की जरूरत होती है। इससे पहले जब साल 2019 में चुनाव हुए थे, तब भी ट्रूडो की पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। जिसके चलते कानून पारित करने के लिए अन्य दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता था।

सिख नेता दिलाएंगे सत्ता

ट्रूडो ने 2015 के चुनाव में अपने दिवंगत पिता एवं पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो की लोकप्रियता का सहारा लिया और चुनाव में जीत हासिल की थी। फिर पार्टी का नेतृत्व करते हुए पिछले दो बार के चुनाव में उन्होंने अपने दम पर पार्टी को जीत दिलायी। फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ट्रूडो पर्याप्त सीटें जीत पाएंगे। 2019 के चुनाव में लिबरल पार्टी बहुमत पाने में सफल नहीं हो पाई थी। उस वक्त जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें समर्थन देकर सरकार में बनाने का मौका दिया था।

महंत नरेन्द्र गिरि को योगी-केशव ने दी श्रद्धांजलि

प्रयागराज, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की प्रयागराज में सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों मौत के बाद मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने उनके बाघंबरी मठ स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी।

योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि को उनके बाघंबरी मठ स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पुलिस के हाथ कई सुराग मिले हैं। मामले की जांच होगी। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह और स्थानीय सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'इस दुखद घटना से हम सभी दुखी हैं। कुंभ के सफल आयोजन में नरेंद्र गिरि का बड़ा योगदान था। पुलिस के चार बड़े अफसर मामले की जांच कर रहे हैं। एक-एक घटना का पदार्फाश होगा। जो भी जिम्मेदार होगा, उसे सजा मिलेगी। दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी बचेगा नहीं, हर हाल में सजा मिलेगी। नरेंद्र गिरि मौत मामले की जांच जारी है इसलिए बेवजह की बयानबाजी से बचना चाहिए।'

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 'उनका जाना संत समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। नरेंद्र गिरि के निधन से बेहद दुखी हूं। संत समाज की ओर से श्रद्धांजलि देने आया हूं। इस दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। यह हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की अपूरणीय क्षति है। मान अपमान की चिंता के बगैर उन्होंने प्रयागराज कुंभ को भव्यता के साथ आयोजित करने में योगदान दिया था। समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर निर्णय में उनका सहयोग प्राप्त होता था। उनकी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री कुंभ में प्रयागराज पधारें, वो आए भी। नरेंद्र गिरि प्रयागराज के विकास को लेकर तत्पर रहते थे। कुंभ में आए श्रद्धालुओं की व्यवस्था और 13 अखाड़ों के बीच समन्वय और आए संतों की व्यवस्था के प्रति लगे रहते थे। साधु समाज, मठ-मंदिर की समस्याओं को लेकर उनका सहयोग प्राप्त होता था। उनके संकल्पों को पूरा करने की शक्ति उनके अनुयायियों को मिले।'

इससे पहले यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि को उनके बाघंबरी मठ स्थित आवास पर अंतिम श्रद्धांजलि दी।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज के अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर प्रयागराज पहुंचे हैं। उन्होंने आज के उन्नाव साथ ही 22 सितंबर को चित्रकूट के दौरे को स्थगित किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज में महंत नरेन्द्र गिरि के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।

इस दौरान केशव मौर्य ने कहा, 'अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच कारकार जो कोई भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। दो दिन पहले ही उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अब वे हमारे बीच ही नहीं है।'

मीडिया से बातचीत में केशव मौर्य ने कहा कि 'यह एक बड़ी साजिश है। अगर कोई साजिश न होती तो महाराज जी आत्महत्या जैसा बड़ा कदम कभी न उठाते। मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है। किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।'

उधर एडीजी लॉ एंड ऑडर प्रशांत कुमार ने कहा कि नरेंद्र गिरि मौत मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है। महंत के शिष्य आनंद गिरि को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को प्रयागराज लाया जा रहा है। हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। सुसाइड नोट के आधार पर गिरफ्तारी की गई है।

गौरतलब हो कि देश में संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरि की सोमवार शाम प्रयागराज में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनका शव अल्लापुर में श्री मठ बाघम्बरी गद्दी के कमरे में मिला। मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने फंदे से लटककर आत्महत्या की है। मौके से आठ पेज का सुसाइड नोट मिला है।

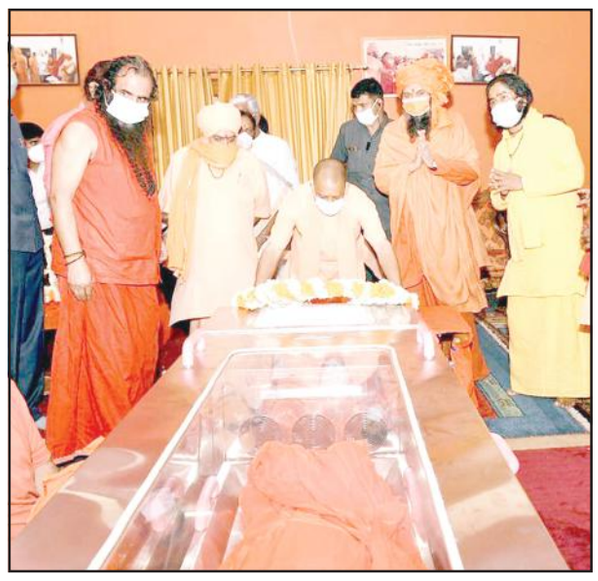

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महंत की मौत को दुखदायी बताया है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी।

इस दौरान कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि 'हम इस घटना से बहुत दुखी हैं। सरकार पूरे मामले की गंभीरता से जांच करा रही है। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कानून मंत्री का बयान एक-एक बिंदु की जांच की जा रही है अपराधी बचेंगे नहीं।'

ज्ञात हो कि देश में संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरि की सोमवार शाम प्रयागराज में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनका शव अल्लापुर में श्री मठ बाघम्बरी गद्दी के कमरे में मिला।

मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने फंदे से लटककर आत्महत्या की है। मौके से आठ पेज का सुसाइड नोट मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महंत की मौत को दुखदायी बताया है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी।

'बिजली हाफ-पानी माफ' के सहारे चुनाव लड़ेगी आप

राजेश अलख

नई दिल्ली, 21 सितम्बर। अगले छह महीने के अंदर जिन पांच राज्यों में देश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें आम आदमी पार्टी 'हाफ बिजली' और मुफ्त पानी को सबसे अहम मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुकी है।

आम आदमी पार्टी अब तक उत्तराखंड, पंजाब, यूपी और गोवा में ये वादा कर चुकी है। जिसके बाद अन्य पार्टियां खासतौर पर जो पार्टी सरकार में है, वो भी 'मुफ्त बिजली' के वादे को 'काउंटर' करने में जुट गई है, लेकिन जो सरकार में नहीं हैं, वो भी इसका ऐलान करने से नहीं चूक रही है।

आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलावर को गोवा में कहा, गोवा में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, बेरोजगारों को 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों पर गोवा के बच्चों का अधिकार होगा। किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। मैं जनता का आदमी हूं, आम आदमी का दर्द समझता हूं।

केजरीवाल के इस वादे पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पलटवार करते हुए उनको उत्तरी गोवा के उनके विधानसभा क्षेत्र सांकेलिम से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी है। साथ ही प्रमोद सावंत ने ये भी कहा कि 'गोवा के लोग बहुत स्मार्ट हैं और वे इस झांसे को गंभीरता से नहीं लेंगे।'

उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी सरकार में आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा चुकी है। जिसके तुरंत बाद राज्य की बीजेपी सरकार ने भी बिजली देने का वादा कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 100 से 200 यूनिट तक खर्च करने पर परिवारों को 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की ओर से हरीश रावत सरकार बनने पर पहले साल 100 यूनिट बिजली मुफ्त और एक साल बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर चुके हैं।

पंजाब में कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में पहले से किसानों और अनुसूचित जाति वर्ग को बिजली मुफ्त मिल रही है। वहां भी आप ने सरकार में आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर दिया है। आप के इस ऐलान के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने पर विचार कर रही है।

उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ग्रामीण उपभोक्ताओं को 2.80 रुपये प्रति यूनिट और बगैर मीटर वालों को 4.07 रुपये प्रति यूनिट की छूट शुरू से ही दे रही है। एक किलोवॉट लोड तक और 100 यूनिट की खपत तक चार रुपये से अधिक प्रति यूनिट छूट दी जाती है। राज्य सरकार ग्यारह हजार करोड़ की सब्सिडी गरीब और किसानों के लिए देती है।

इन हालात में आम आदमी पार्टी सभी को मुफ्त बिजली और पुराने बिलों की माफ करने का ऐलान किया है।

मध्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी मध्यप्रदेश में भी विधानसभा एवं नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी। दिल्ली फॉर्मूले की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी बिजली-पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला यात्रा फ्री की जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आप के हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज रत्नेश गुप्ता के अनुसार नवंबर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

गुजरात में सूरत नगर निगम चुनाव में इस साल 27 सीटें जीतने के बाद गांधी नगर के नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी आप पहले से ही गुजरात विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आप संयोजक केजरीवाल बीजेपी के 25 साल के शासन के बाद भी गुजरात में महंगी बिजली पर सवाल उठा चुके हैं।

जापान में 4 अक्टूबर को तय होगा नया पीएम

टोक्यो, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। जापान सरकार ने मंगलवार को नवंबर में होने वाले आम चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री का निर्धारण करने के लिए 4 अक्टूबर को असाधारण संसद सत्र बुलाने के अपने फैसले की घोषणा की। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 29 सितंबर को होने वाले सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व के चुनाव से निवर्तमान प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा के अगले प्रमुख को प्रभावी ढंग से तय करने की उम्मीद है, जो इस महीने के अंत में इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि एलडीपी शक्तिशाली निचले को नियंत्रित करता है। चार उम्मीदवारों, पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा, पूर्व संचार मंत्री सानाए ताकाची, टीकाकरण मंत्री तारो कोनो और एलडीपी के कार्यकारी कार्यवाहक महासचिव सीको नोडा ने एलडीपी दौड़ के लिए अपनी बोलियों की घोषणा की है।

नए प्रधानमंत्री द्वारा उसी दिन एक नया मंत्रिमंडल शुरू करने और बाद में उप मंत्रियों और अन्य कर्मियों पर निर्णय लेने की उम्मीद है।

सभी चार उम्मीदवारों ने कहा है कि वे एक नीति भाषण देंगे और निर्वाचित होने पर विपक्षी दलों के साथ सवाल-जवाब का सत्र आयोजित करेंगे। इस मामले में, आम चुनाव के लिए दो सबसे संभावित समय सारिणी 26 अक्टूबर को 7 नवंबर को मतदान के लिए प्रचार शुरू करना है या 2 नवंबर को 14 नवंबर को मतदान के लिए प्रचार करना है।

चार उम्मीदवारों के उद्योग समूहों और स्थानीय संगठनों पर विचारों का आदान-प्रदान जारी रखने का अनुमान है।

गुरुवार से, उन्हें चार दिनों तक चलने वाले ऑनलाइन नीति बहस सत्रों में जनता के सवालों के जवाब देने की योजना है। प्रतिनिधि सभा का अगला चुनाव 21 अक्टूबर के बाद के महीनों में होने की उम्मीद है जब मौजूदा निचले सदन के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

समन की तारीख पर ब्यूटी पार्लर में बैठी थीं अभिषेक बनर्जी की पत्नी : ईडी

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी बनाए गए तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने चौंकाने वाले दावे किये हैं। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया गया कि समन की तारीख पर रुजिका दिल्ली के एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद थीं। रुजिका बनर्जी ने इससे पहले ईडी से मिले समन में पेश होने से बचने के लिए कहा था कि वो पटना में मौजूद हैं। लेकिन जांच एजेंसी का कहना है कि जिस दिन उन्हें जांच में शामिल होना था उस दिन वो पटना में नहीं बल्कि दिल्ली के एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद थीं। निदेशालय का यह भी दावा है कि उसके पास इससे संबंधित सबूत भी हैं।

हालांकि, एजेंसी के दावे को बनर्जी के वकीलों ने खारिज किया है। रुहिला बनर्जी के वकीलों का कहना है कि वो दिल्ली के ब्यूटी पार्लर में जरुर गई थीं लेकिन उस दिन नहीं जिस दिन उन्हें पेश होना था। पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पत्नी ने अदालत में एक याचिका दायर की थी। जिसमें यह मांग की गई थी कि ईडी के समन को निरस्त कर दिया जाए।

अदालत में इस याचिका पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ईडी की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने अदालत में कहा कि, 'हमारे पास यह दिखाने के लिए सबूत है कि उस तारीख पर अभिषेक बनर्जी की पत्नी दिल्ली के एक पार्लर में मौजूद थीं। जिस तारीख पर उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था।' हालांकि, तारीख का जिक्र किये बिना उन्होंने कहा कि महिला का दावा है कि वो पटना में थीं, लेकिन वो दिल्ली में थीं।

एएसजी ने आगे कहा, 'अगर वो ब्यूटी पार्लर के लिए दिल्ली आ सकती हैं, तब वो जांच के लिए भी आसकती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवाश हमारे अधिकारियों के पास वो सर्विस नहीं है जो ब्यूटी पार्लर में मिलता है।' बनर्जी कपल की तरफ से अदालत में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी के इस दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की बहस की उम्मीद ईडी से नहीं की जा सकती है। महिला दिल्ली में मौजूद थीं, लेकिन उस दिन नहीं जिस दिन उन्हें ईडी के सामने पेश होना था।

आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने 10 सितंबर को ईडी की तरफ से मिले उस समन का विरोध किया था जिसमें उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए 21 सितंबर को दिल्ली स्थित उसके कार्यालय में पेश होने के लिए कहा था। कपल ने अदालत से मांग की थी कि वो ईडी को यह भी निर्देश दे कि वो उन्हें दिल्ली में उपस्थित होने के लिए समन ना भेजें।

33 साल के अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा सासंद हैं और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों को 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन का पता चला है। जांच एजेंसी का मानना है कि कोयले की तस्करी के माध्यम से कुछ ही महीनों में ये सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं।

बहरहाल दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर तय की है और ईडी को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है।

राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जा सकते है सोनोवाल

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को असम की राज्यसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है क्योंकि विपक्ष ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है।

केंद्रीय जहाजरानी मंत्री ने असम विधानसभा में निर्वाचान अधिकारी दुलाल पेगू के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा, अगप और यूपीपीएल वाले राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के सर्वसम्मत उम्मीदवार हैं।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, अगप नेता एवं कृषि मंत्री अतुल बोरा, यूपीपीएल नेता एवं हथकरघा और कपड़ा मंत्री यू जी ब्रह्मा, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के प्रमुख प्रमोद बोडो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाबेश कलिता, और कैबिनेट मंत्री और भाजपा के कई अन्य नेता उनके साथ थे।

असम विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद बिस्वजीत दैमारी के उच्च सदन से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा की यह सीट खाली हुई है। वह वर्तमान में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं।

सोनोवाल इस साल मई में लगातार दूसरी बार माजुली से विधानसभा के लिए चुने गए थे। 59 वर्षीय भाजपा नेता को जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 22 सितंबर है, जबकि 23 सितंबर को पर्चा की जांच की जाएगी और नतीजे चार अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

सोनोवाल की जीत निश्चित लग रही है क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है।

सोनोवाल ने उन्हें सेवा का अवसर देने के लिए असम के लोगों का आभार व्यक्त किया और सभी का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने प्रधानमंत्री और माजुली के लोगों को भी धन्यवाद दिया।

सोशल/डिजिटल मीडिया एडवाइजरी पर बैठक सम्पन्न

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 21 सितम्बर। सोशल/डिजिटल मीडिया एडवाइजरी और राज्य आईपीआर विभाग के साथ डिजिटल मीडिया के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देशों से संबंधित दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों की रूपरेखा पर चर्चा के लिए आज तादोंग के सूचना भवन में हितधारकों की एक परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आईपीआर सचिव सिफोरा जी. तार्गेन ने की।

बैठक में आईपीआर विभाग के निदेशक बेनू गुरुंग, एसपी क्राइम तेनजिंग लोडेन लेप्चा, प्रेस क्लब आफ सिक्किम, जर्नलिस्ट यूनियन आफ सिक्किम, पत्र सूचना कार्यालय और डिजिटल मीडिया हाउस के प्रतिनिधि और आईपीआर विभाग के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। यह जानकारी आईपीआर विभाग ने दी है।

बैठक में आईपीआर विभाग द्वारा तैयार किए गए दो दस्तावेजों पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य पत्रकारिता की नैतिकता को सुनिश्चित करते हुए राज्य में डिजिटल मीडिया हाउस के लिए कार्य वातावरण प्रदान करना है। एडवाइजरी में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा अनुशंसाओं के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के प्रावधान, प्रेस काउंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचार संहिता, आईटी अधिनियम 2000 और आईपीसी की प्रासंगिक धाराएं शामिल हैं।

आईपीआर विभाग के सचिव ने कहा कि सिक्किम में सोशल/डिजिटल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एडवाइजरी राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को स्वीकार करते हुए डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में शिष्टाचार सुनिश्चित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अधिकांश लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोगों को सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण है ताकि लोगों को एक सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव मिल सके। सचिव ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग दो महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले आज की बैठक की प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया जाएगा।

विभाग के निदेशक ने इन दोनों दस्तावेजों के महत्व को समझाते हुए बताया कि विभाग ने वर्ष 2019 से इस पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि हितधारकों समेत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ बार-बार परामर्श के बाद खाका तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक इस संबंध में अंतिम परामर्श बैठक थी और अब दस्तावेज सरकार को मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे।

वहीं, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी ने विभाग की पहल का स्वागत किया और एडवाइजरी के संबंध में अपने सुझाव रखे। मीडिया प्रतिनिधियों ने भी दोनों दस्तावेजों पर अपने सुझाव रखे। बताया गया है कि बैठक के फीडबैक और सुझावों को दस्तावेज में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

चीन से लगी सीमा पर युद्ध के नये प्रतिमान का सामना कर रहा है भारत : राहुल

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन की ओर से सीमा के निकट सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किये जाने संबंधी खबर का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि भारत अपनी सीमा पर युद्ध के नये प्रतिमान का सामना कर रहा है।

उन्होंने ट्वीट किया, सीमा पर हम एक युद्ध के नये प्रतिमान का सामना कर रहे हैं। इसे नज़रअंदाज़ करने से काम नहीं चलेगा।

कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की, उसमें कहा गया है कि चीन ने लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के निकट 10 नये एयर बेस का निर्माण कर लिया है तथा भारतीय सीमा के निकट वह अपनी अन्य सैन्य आधारभूत अवसंरचना को भी मजबूत कर रहा है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com